सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 330, नई दिल्ली । गुरुवार, 08 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी।

03 सदन की कार्यवाही तीसरे दिन भी चढ़ी हंगामे की भेंट
06 न्याय प्रणाली में सुधार कैसे हो?
08 मातंग ऋषि की पुत्री श्रृंगार लहरी की प्रस्तुती में श्रृंगार रस को किया जीवन्त

नोएडा की कई सड़कें बंद, दिल्ली जाने वाले रास्ते प्रभावित; किसानों के संसद घेराव पर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी...

किसानों की महापंचायत और दिल्ली मार्च को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट हो गई है...

संजय बाटला

किसानों ने दिल्ली के संसद भवन का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। किसानों की महापंचायत और दिल्ली मार्च को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट हो गई है। प्रदर्शन और दिल्ली कूच के कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार को नोएडा की कई सड़कों पर आगमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दिल्ली जाने वाले भी कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित होगी।

नोएडा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान बृहस्पतिवार को नोएडा से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली के संसद भवन का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। किसानों की महापंचायत और दिल्ली मार्च को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट हो गई है।

नोएडा के कई मार्ग पर आगमन प्रभावित

किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से देर शाम तक सेक्टर-1 गोलचक्कर चौक से सेक्टर-6 चौकी चौक तक, संदीप पेपर मिल चौक से हरौला चौक तक मार्ग पर यातायात का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।

धरना प्रदर्शन के मद्देनजर सेक्टर-1 गोलचक्कर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर-6 चौकी चौक, झुंडपुरा चौक, सेक्टर-8, सेक्टर-10, सेक्टर-11, सेक्टर-112 चौक, हरौला चौक से आवश्यकतानुसार यातायात का डायवर्जन किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन के दौरान सुरक्षित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते है।

ऐसा रहेगा यातायात

गोलचक्कर चौक सेक्टर-1 से संदीप पेपर मिल चौक होकर झुंडपुरा चौक की ओर जाने वाला यातायात गोलचक्कर चौक सेक्टर-1 से रजनीगंधा चौक होकर गंतव्य को जा सकेगा।

झुंडपुरा चौक से संदीप पेपर मिल चौक होकर गोलचक्कर चौक सेक्टर-1 की ओर जाने वाला यातायात झुंडपुरा चौक से सेक्टर-8, सेक्टर-10, सेक्टर-11, सेक्टर-112 चौक होकर गंतव्य को जा सकेगा।

संदीप पेपर मिल चौक से हरौला चौक होकर जाने वाला यातायात रोहन मोटर्स तिराहा, आईजीएल चौक सेक्टर-1 से गोलचक्कर चौक और अशोक नगर होकर गंतव्य को जा सकेगा।

हरौला चौक से संदीप पेपर मिल चौक की जाने वाला यातायात हरौला चौक से सेक्टर-16 मार्किट कट होकर गंतव्य को जा सकेगा।

गोलचक्कर चौक से रजनीगंधा चौक होकर सेक्टर-18, सेक्टर-27, सेक्टर-37 आदि की ओर जाने वाला यातायात यथावत गंतव्य को जा सकेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से और एमपी-1 मार्ग से डीएनडी होकर दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में चिल्ला रेड लाइट से गंतव्य को जा सकेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से चिल्ला रेड लाइट होकर दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात चिल्ला रेड लाइट पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में डीएनडी से गंतव्य को जा सकेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से आकर महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की डीएनडी से गंतव्य की ओर जा सकेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से आकर महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में चरखा गोलचक्कर से सेक्टर-94 अंडरपास होकर महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37, सेक्टर-18, सेक्टर-16, सेक्टर-15 से अशोक नगर होकर गंतव्य को जा सकेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से आकर डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में दलित प्रेरणा स्थल गेट नंबर-2 सेक्टर-95 (बर्ड फिडिंग प्वाइंट) के निकट फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-18 चढ़ने वाले लूप से सेक्टर-18, सेक्टर-16, सेक्टर-15 से अशोक नगर और एलिवेटेड रोड होकर सेक्टर-60, सेक्टर-62, एनएच-24 होकर गंतव्य को जा सकेगा।

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र
Title Code : DELHIN28985
PARIVAHAN VISHESH NEWS

1. Web Portal https://www.newsparivahan.com/
2. facebook https://www.facebook.com/newsparivahan00
3. Twitter https://twitter.com/newsparivahan
4. Linkedin https://www.linkedin.com/in/news-parivahan-169680298/
5. Instagram https://www.instagram.com/news_parivahan/
6. Youtube https://www.youtube.com/@NewsParivahan

पर आप सभी के लिए 24 घण्टे उपलब्ध

3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, A-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली : 110063
सम्पर्क : 9212122095, 9811732095

www.newsparivahan.com, www.newstransport.in
Info@newsparivahan. com, news@newsparivahan.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर बड़ा हादसा, अचानक ब्रेक मारने से ट्रक में घुसी कार; चालक समेत दो की मौत

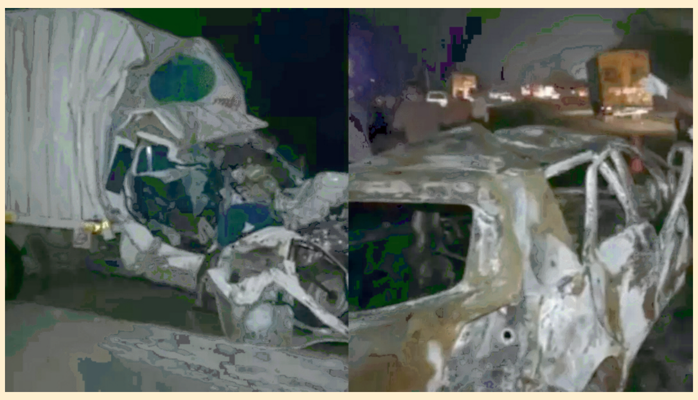

परिवहन विशेष न्यूज

बताया गया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक जैसे एक बड़े वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दी। जिससे सेंट्रो कार उससे जा टकराई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मामचंद और दिनेश को निकाला जा सका और अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पटौदी। बिलासपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बीती रात एक बड़े वाहन के ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उससे टकरा गई। हादसे में कार चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ओल्ड राव होटल से पहले हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि राजस्थान के खैरथल जिले के जालावास गांव के रहने वाले मामचंद यादव ड्राइवरी का काम करते थे। वह अपने ही गांव के दिनेश कुमार सोनी की सेंट्रो कार से दिनेश सोनी के साथ उनके बेटे प्रवीण सोनी को छोड़ने फरीदाबाद गए थे।

कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त

वापस जाते समय रास्ते में ओल्ड राव होटल से पहले फ्लाई ओवर पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। थाने में दी शिकायत में मामचंद के बेटे ने कहा कि हाईवे पर ट्रक जैसे एक बड़े वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दी। जिससे सेंट्रो कार उससे जा टकराई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

आसपास के लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद मामचंद और दिनेश को निकाला जा सका। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर थाना क्षेत्र में ही पिछले एक माह में ही 10 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

जल्द शुरू होगा द्वारका एक्सप्रेसवे...

केंद्रीय मंत्री गडकरी और राव इंद्रजीत के साथ बैठक में बनी सहमति...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके लिए मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक में गुरुग्राम के हिस्से वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को खोलने के लिए सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं।

राव इंद्रजीत ने अगले 15 दिन में एक्सप्रेसवे शुरू होने की उम्मीद जताई है। उधर, मौखिक आदेशों के बाद अब एनएचएआई के अधिकारी भी द्वारका एक्सप्रेसवे को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस माह लोगों को इस मार्ग पर यातायात की सुविधा मिलने लगेगी। जल्द ही औपचारिक रूप से इसके लोकार्पण की भी घोषणा की जाएगी।

इस वर्ष जिला से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाएं धरातल पर साकार होंगी। कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू होगा। जिला उपायुक्त निशांत कुमार पहले ही द्वारका एक्सप्रेसवे को फरवरी माह में शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। इस संदर्भ में सरकार के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी पत्र भेजा जा चुका है। उधर, मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी अगले 15 दिनों में एक्सप्रेस वे को शुरू करने की सहमति दी है।

एक्सप्रेसवे को चार हिस्सों में किया गया है विभाजित

एक्सप्रेसवे को चार हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला हिस्सा महिपालपुर के पास शिव मूर्ति से द्वारका तक का है। दूसरा द्वारका अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर) से बजघेड़ा तक है।

तीसरा हिस्सा बजघेड़ा से बसई रेल ओवरब्रिज (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) का है। चौथा हिस्सा बसई आरओबी से खेड़की दौला तक है। इसमें गुरुग्राम में पड़ने वाले राजमार्ग के हिस्से में क्लोवरलीफ इंटरचेंज शामिल है, यह

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (एनएच-48) और खेड़की दौला के पास दक्षिणी पेरिफेरल रोड (एसपीआर) को जोड़ेगा।

खेड़की दौला टोल शिफ्ट कराने पर भी चर्चा

बैठक में खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने की भी चर्चा की गई। राव ने बताया कि टोल की समय अवधि पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार भी टोल शिफ्ट करने के लिए दूसरी जगह देने को तैयार है। ऐसे में जल्द से जल्द इस टोल को शिफ्ट किया जाए। गडकरी ने राव को बताया कि टोल वसूली के लिए नई योजना तैयार कर ली गई है।

गुरुग्राम-रेवाड़ी-पटौदी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण धीमा

राव इंद्रजीत ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि कंपनी गुरुग्राम-रेवाड़ी-पटौदी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर गंभीर नहीं है। निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा की गई है। इस दौरान निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा कर लें।

एनएचएआई बनाएगा होंडा से उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड

केंद्रीय मंत्री ने गडकरी से गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड बनाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के नोटिफिकेशन के अनुसार हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक एनएचएआई का भाग था। उसके बावजूद अधिकारियों ने इसको एलिवेटेड बनाने के स्थान पर डी स्कोप कर दिया। राव ने गडकरी को बताया कि यह नीतिगत कार्य नहीं है। राव ने गडकरी को 2017 का नोटिफिकेशन दिखाया। इसमें इस रोड को एनएचएआई का भाग माना गया है।

गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस रोड को पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार एनएच का हिस्सा माना जाए। इसे एलिवेटेड बनाने की योजना तैयार की जाए। बैठक में मौजूद जीएमडीए के अधिकारियों ने कहा कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अतिक्रमण भी तेजी से हटाया जा रहा है। जीएमडीए के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ही किया जाता है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सर्वर डाउन होने की समस्या मंगलवार को भी बनी रही। एक सप्ताह से चली आ रही इस समस्या के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

आरटीओ कार्यालय में सर्वर खराब होने से कामकाज ठप

देशव्यापी समस्या के समाधान में एक दो दिन और लगने के आसार

परिवहन विशेष न्यूज

समस्या के चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट देने पहुंचे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से बिना टेस्ट दिए वापस जाना पड़ा। अधिकारियों की माने तो मंगलवार को कुछ ही कार्यालयों में सर्वर चल सके। अन्य कार्यालयों में कामकाज नहीं हो सका।

नई दिल्ली। राजधानी में आरटीओ कार्यालय में सर्वर न चलने की समस्या से विभागीय कर्मी ही नहीं आम लोग भी परेशान हैं। एक सप्ताह से चली आ रही इस देशव्यापी समस्या के चलते न तो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बन पा रहे हैं और न ही अन्य कामकाज हो रहा है।

समस्या के चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट देने पहुंचे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से बिना टेस्ट दिए वापस जाना पड़ा। अधिकारियों की माने तो मंगलवार को कुछ ही कार्यालयों में सर्वर चल सके। अन्य कार्यालयों में कामकाज नहीं हो सका। समस्या के समाधान में एक दो दिन और लगने की संभावना है।

आरटीओ कार्यालयों में सर्वर डाउन होने की समस्या मंगलवार को भी बनी रही। एक सप्ताह से चली आ रही इस समस्या के चलते कार्यालयों में लाइसेंस बनवाने गए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेषरूप से वह लोग परेशान नजर आए, जिन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए मंगलवार का स्लॉट मिला था। इनमें से कई ऐसे भी थे, जिन्होंने स्लॉट के चलते अपने कार्यालय या कामकाज से अवकाश लिया था। उन्हें घंटों का इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौटना पड़ा।

लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने पहुंचे मोहम्मद असलम ने बताया कि वह दो पहिया चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने सराय काले खां स्थित आरटीओ कार्यालय गए थे। उनके जैसे और भी कई लोग पहले से वहां मौजूद थे। पता चला कि सर्वर डाउन है। ऐसे में टेस्ट नहीं लिया जाएगा। घंटों इधर-उधर घूमने के बाद भी किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। यह भी नहीं बताया गया कि कब टेस्ट देने आना है।

दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में भी दिक्कत

इस मामले में आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तक सर्वर ठीक होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि कुछ कार्यालयों में सर्वर के अटक-अटक कर काम करने से थोड़ा बहुत कामकाज हुआ। अन्य कार्यालय में कामकाज ठप रहा। उन्होंने बताया कि यह समस्या एक दो दिन में दुरुस्त होने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद ही लाइसेंस के लिए टेस्ट लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सर्वर का प्रबंधन एनआईसी के द्वारा किया जाता है।

लोगों ने बयां किए अपने हालात

वहीं, सराय काले खां दो पहिया वाहन लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने आए रोहित ने बताया कि वह उन्होंने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए स्लॉट दिया गया था। यहां आकर पता लगा कि सर्वर ठप है। शाम तक इंतजार किया, लेकिन काम नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि अब दोबारा अवकाश लेकर आना होगा।

घर को ना बनाएं कोप भवन

जब राजा दशरथ को सूचना मिली कि उनकी एक रानी कैकई कोप भवन में है, तो कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ का कलेजा धक सा रह गया। उस समय महलों में एक भवन ऐसा होता था, जिसे कोप भवन कहते थे। जब किसी सदस्य का मन ठीक न हो, वह गुस्से में हो तो कोप भवन में चला जाता था। इसके बाद मतभेद और विवादों की बातें वहीं होती थीं।

राजा दशरथ कैकयी के पास कोप भवन में पहुंचे। वहां कैकयी ने उनसे दो वरदान मांग लिए। नतीजे में राम राज्य चौदह वर्षों के लिए आगे बढ़ गया।

इस किस्से में कोप भवन को समझना बहुत जरूरी है। आजकल घर बड़े-बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें पहले की तरह कोप भवन नहीं होता है। आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन बन जाता है। परिवार के लोग मूड खराब करने के लिए ड्रॉइंग रूम, बेडरूम या डायनिंग रूम नहीं देखते हैं, कहीं भी गुस्सा कर लेते हैं। कोप भवन का अर्थ है कि घर का वह स्थान जहां से नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जिस तरह की हम विचार करते हैं इन विचारों का प्रभाव हमारे शरीर के साथ-साथ हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है और यहां तक की हमारे घर की वस्तुओं व घर के दीवारों पर भी पड़ता है।

बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है कि आपकी प्रत्येक सांस का प्रभाव आपके आसपास की वस्तुओं पर धीरे-धीरे पड़ता रहता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से आप और हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से हमारा घर और घर की दिवारें भी सांस लेती हैं। साथ ही साथ हमारी मुस्कुराहट, हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट और उनकी छोटी-छोटी खुशियों से भरी शरारतें, बुजुर्गों को जितनी खुशी होती है उससे सदैव उनके आशीर्वाद की वर्षा होती रहती है। इसके अलावा घर परिवार की स्त्रियों के प्रति सम्मान और पुरुषों के विशेष सामर्थ्य से ही घर की दिवारें हमेशा प्रसन्न रह

सकती हैं। बस एक सीधा सा सिद्धांत है जितने आपके घर परिवार के लोगों में प्यार- संतोष- खुशियां- शांति है उतना ही आपके घर- मकान कि प्रत्येक वस्तुओं में यहां तक की उसकी दीवारों में सुकून व शांति है और ऐसा घर आपको मंदिर जैसी शांति प्रदान करेगा।

ध्यान रहे : घर के सदस्यों के बीच जब भी वाद-विवाद हो तो विचार-विमर्श शांति के साथ करना चाहिए और प्रेम के साथ मतभेदों को दूर करना चाहिए। अवसाद व विवाद का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए, उसे लंबा खींचकर घर को कोप भवन नहीं बनाना चाहिए।

भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा का रहस्य

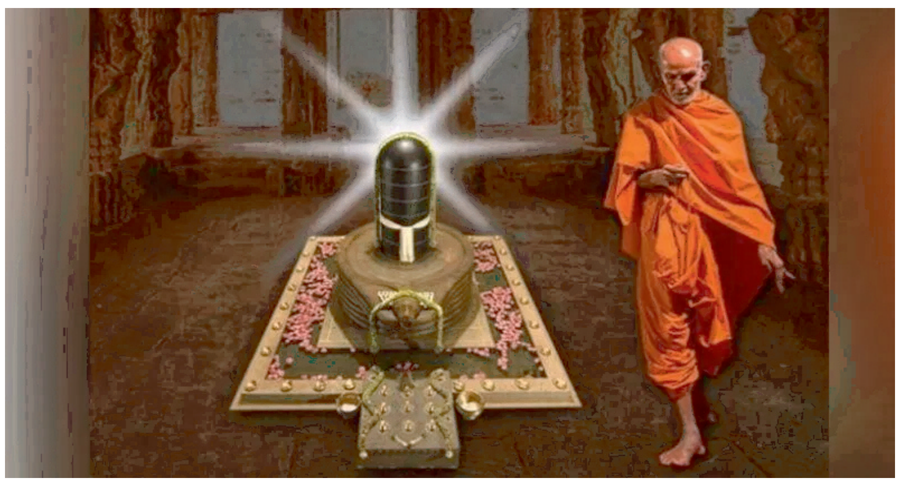

शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान है। वह इसलिए कि शिव के सोमसूत्र को लांघा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आप ने आसमान में अर्ध चंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है।

अर्द्ध सोमसूत्रांतमित्यर्थः शिव प्रदक्षिणीकुर्वन सोमसूत्र न लंघयेत, इति वाचनान्तरात।

सोमसूत्र : शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र की कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है, वहीं सोमसूत्र का स्थान होता है।

क्यों नहीं लांघते सोमसूत्र :- सोमसूत्र में शक्ति-स्रोत होता है अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 5 अन्तस्थ वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है। जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्ध चंद्राकार प्रदशिक्षा ही करने का शास्त्र का आदेश है।

तब लांघ सकते हैं :- शास्त्रों में अन्य स्थानों पर मिलता है कि तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके हुए सोम सूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है। लेकिन शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा का मतलब शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए।

किस ओर से करनी चाहिये परिक्रमा :- भगवान शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बांई ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें।

यू.सी.सी. :- महिलाओं को संवैधानिक रूप से सशक्त करेगा

(तलाक के मामलों में भी महिलाओं को संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त रहेगा। इसी के साथ प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत जनजाति समुदाय की महिलाओं के अधिकारों को अधिक सशक्त और सुरक्षित किया जा सकेगा।)

भारत के सभी वर्गों की महिलाओं को अधिक सशक्त करने का काम करेगा 'समान नागरिक संहिता कानून'।

जब भी बात आती है महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलने की तब वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने मे कही ना कही कमजोर दिखाई पड़ता हैं। क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वालें लोग निवास करते हैं।

किंतु संविधान के आधार पर हिंदू सहित सभी भारतीय धर्म जिसके अंतर्गत जैन, सिख, बौद्ध धर्म आते है। ऐसे सभी धर्मों के मानने वालों के लिए संवैधानिक कानूनों का निर्माण कर दिया गया। जिसके अंतर्गत हिंदू मेरिज एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू अवयस्कता और संरक्षक अधिनियम जैसे कानूनों का निर्माण कर महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने का प्रयास किया गया। जबकि हिंदू धर्म में सांस्कृतिक आधार पर एवं भारतीय शास्त्रों में प्रारंभ से ही स्त्री-पुरूष को समान माना गया हैं और दोनों ही वर्गों को अपने समान अधिकार भी प्रदान कियें गयें हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त अर्द्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ही समानता का भाव जागृत करता हैं। ऐसे में हिंदुओं सहित सभी भारतीय मूल धर्मों में संवैधानिक समानता को सहर्ष स्वीकार किया गया है। किंतु बाकि अन्य धर्मों को जिसके अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी आते है। उन्हें उनके धार्मिक नियमों के आधार पर पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की व्यवस्था संविधान में की गयी हैं। परंतु लगातार वर्षों से समय समय पर एक बात निकलकर आती हैं कि महिलाओं को उनके नैतिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा हैं। और मुख्यतः जिन धर्मों के अपने पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। उनमें परेशानी अधिक दिखाई पड़ रही है। इसका एक उदाहरण 'तीन तलाक' के रूप मेन सभी के सामने में स्थापित हैं।मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं को मान्यता प्राप्त हैं। जबकि संवैधानिक रूप से तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं गैर कानूनी हैं। ऐसे ही ईसाई में भी बाईबल को आधर मानकर चर्च के नियमों को सर्वोपरि माना जाता रहा हैं। हिंदूओं सहित जैन, बौद्ध और सिख समुदाय में हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हैं। किंतु मुस्लिम समुदाय में विवाह की आयु तय नही हैं उनके धर्म के अनुसार जब भी लड़की अपने मासिक धर्म के चक्र में प्रवेश करती हैं। तभी से वह विवाह योग्य मानी जाने लगती हैं। ऐसे ही अनेक उदाहरण है जिनके आधार पर संवैधानिक व्यवस्था के चलते भी महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता हैं और स्त्रीयों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता हैं। भारत के प्रत्येक समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती देगा यू.सी.सी. कानून। महिलाओं में विवाह की न्यूनतम आयु की समानता से लेकर संतान गोद लेने तक के अधिकारों में समानता प्रदान करने का काम होगा। इसी के साथ उत्तराधिकार के आधार पर महिलाओं को मिलने वाली पारिवारिक सम्पत्ति में बराबर भागीदारी के अधिकार को भी संरक्षित करने का काम हो सकेगा। तलाक के मामलों में भी महिलाओं को संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त रहेगा। इसी के साथ प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत जनजाति समुदाय की महिलाओं के अधिकारों को अधिक सशक्त और सुरक्षित किया जा सकेगा। यू.सी.सी. के लागू होने के बाद भी वर्तमान में जनजाति वर्ग को मिलने वालें सभी अधिकार और सुविधाएं यथावत रहेंगे। इसी के साथ जनजाति समुदाय की महिलाओं को भी भारत की अन्य महिलाओं के समान पारिवारिक सम्पत्ति में बराबरी की भागीदारी मिल सकेंगे। जनजाति महिलाओं में भी विवाह की न्यूनतम आयु सभी के समान मानी जाने लगेगी। जिससे जनजाति वर्ग की लड़कियों को अधिक अधिकार मिल सकेंगे, जिसके चलते जनजाति वर्ग की महिलाओं के द्वारा शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ रहने वाली महिलाओं को संबल प्रदान किया जा सकेगा। समान नागरिक संहिता के आने पर किसी भी वर्ग के धार्मिक एवं नागरिक अधिकारों हनन नहीं हो सकेगा। सभी वर्ग के अधिकारों को अधिक सशक्त और संरक्षित करने में संवैधानिक प्रावधान लागू हो सकेंगे।

आप भी बनना चाहती हैं इंडिपेंडेंट, महिलाएं इन 5 चीजों पर करें फोकस, इन तरीकों से बढ़ाएं पहला कदम

कई बार महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बन पाना आसान नहीं होता है. लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट वुमेन होने की ख्वाहिश रखती हैं. तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और आत्मविश्वास जैसी चीजों पर फोकस करके आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा सकती हैं.

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का रास्ता कई बार काफी मुश्किल होता है. ऐसे में इंडिपेंडेंट बनने के लिए ज्यादातर महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किन बातों पर फोकस करना जरूरी होता है.

कई बार चाहकर भी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सी महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट होना काफी मुश्किल भरा टास्क होता है. ऐसे में अगर आप कुछ चीजों पर फोकस करते हुए आगे कदम बढ़ाती हैं, तो आत्मनिर्भर बनने का आपका रास्ता आसान हो सकता है. तो आइये जानते हैं इसके बारे में.

सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है जरूरी

आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये आपका पहला कदम हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फीडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें. साथ ही प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक के डिसीजन आप खुद पूरे विश्वास के साथ लेने का प्रयास करें. इतना ही नहीं अगर कोई फैसला गलत भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पर न डालकर आप खुद ही लें.

फैसले लेना सीखें

ज्यादातर घरों में महिलाएं हर छोटा-बड़ा फैसला घर में किसी न किसी से पूछ कर ही लेती हैं. ऐसे में उनको फैमली मेम्बर्स या पार्टनर पर निर्भर रहने की आदत हो जाती है. लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद में डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें. जिससे आप जरूरत पड़ने पर खुद फैसला लेने में सक्षम रहें.

भावनात्मक रूप से मजबूत बनें

आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका भावनात्मक रूप से मजबूत बनना भी बहुत जरूरी है. इसलिए अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जगह अपनी केयर खुद करना सीखें. इस तरह से आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहेंगी और खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रखने में कामयाब हो सकेंगी.

फाइनेंस मैनेज करना सीखें

बहुत सी महिलाएं जॉब करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहती हैं. वहीं ज्यादातर महिलाएं फाइनेंस से जुड़े डिसीजन बिना किसी की इजाजत के लेने में हिचकिचाने लगती हैं. जबकि आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि अपने बजट से लेकर इंवेस्टमेंट तक का हिसाब आप खुद रखें. इसलिए इंडिपेंडेंट बनने के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना सीखें.

- अब तक दो बार स्थगित हो चुकी है निगम सदन की बैठक
- महापौर का विवेकाधिकार फंड बढ़ाने पर भाजपा पार्षद कर रहे हैं विरोध
- महापौर ने कहा कि वह रात 12 बजे तक चलाएगी निगम

सदन की कार्यवाही तीसरे दिन भी चढ़ी हंगामे की भेंट, नहीं हो पाई बजट पर चर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

एमसीडी सदन में तीसरे दिन भी हंगामे के कारण बजट पर चर्चा नहीं हो पाई। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान पर एमसीडी की विशेष बैठक में इस पर चर्चा होनी थी। बुधवार को निगम सदन की बैठक अब तक दो बार स्थगित हो चुकी है। भाजपा पार्षद महापौर का विवेकाधिकार फंड 9 करोड़ से 15 करोड़ किए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वर्ष 2023-24 संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान पर दिल्ली नगर निगम की सदन की विशेष बैठक में तीसरे दिन भी सही तरीके से चर्चा नहीं हो पाई। बुधवार को निगम सदन की बैठक अब तक दो बार स्थगित हो चुकी है।

भाजपा पार्षद महापौर का विवेकाधिकार फंड 9 करोड़ से 15 करोड़ किए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं, महापौर डा. शैली ओबेराय ने सदन में सभी पार्षदों को चेतावनी दे दी है कि वह बजट चर्चा कराकर रहेगी चाहे रात के 12 क्यो न बज जाए।

दिल्ली नगर निगम की बजट पर चर्चा सोमवार से शुरू हुई थी। पहले दिन तो 18 पार्षदों ने चर्चा में भाग लेते हुए बजट पर सुझाव दिए थे, लेकिन मंगलवार को जैसे ही भाजपा पार्षदों के पास कट मोशन (बजट संशोधन) के प्रस्तावों की प्रतियां पहुंची वैसे ही भाजपा पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया था। इसकी वजह से मंगलवार को निगम सदन की बैठक स्थगित हो गई थी।

मेयर के आसन के सामने प्रदर्शन

बुधवार को दोपहर 2.38 मिनट पर निगम सदन की बजट बैठक शुरू हुई तो भाजपा पार्षद महापौर के आसन के सामने आ गए। इसके बाद महापौर ने बैठक को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद फिर 3.38 पर निगम की बैठक फिर शुरू हुई तो भाजपा पार्षद फिर महापौर के आसन के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद आप पार्षदों ने भी नारेबाजी कर दी।

दोनों ओर से नारेबाजी के बीच भाजपा पार्षद महापौर आसन के पास रखीं कुर्सियों और मेज पर चढ़ गए और कट मोशन प्रस्तावों का विरोध करने लगे। हंगामा बढ़ते देख महापौर ने फिर सदन की बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी है।

12 बजे तक कराऊंगी बजट पर चर्चा: डॉ. शैली ओबेराय

बजट चर्चा में भाजपा के हंगामे के बीच महापौर डॉ. शैली ओबेराय ने चेतावनी दे दी है कि वह रात 12 बजे तक निगम सदन चलाएगी और बजट पर चर्चा कराकर रखेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी निगम सदन की बैठक स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर रातभर चली। इस दौरान भाजपा पार्षदों और आप पार्षदोंके बीच हाथापाई हुई थी।

अरविंद केजरीवाल के सामने नई मुसीबत! 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी; आप ने कहा- कानून के अनुसार कार्रवाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। कोर्ट के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे।

नई दिल्ली। बार-बार ईडी के समन को ठुकराने पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा है।

कोर्ट के समन पर AAP की प्रतिक्रिया

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। आप ने कहा कि हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे।

केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए- भाजपा

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कानून से बच नहीं सकते हैं। नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की अपनी प्रतिबद्धता बदल दी है।

खास बात है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच बार समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 18 जनवरी, तीन जनवरी, दो नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था।

अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित, सरकारी गवाह बनने की जताई थी इच्छा....

आतंकवादी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में आरोपित न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सरकारी गवाह बनने के आधार पर अमित चक्रवर्ती ने जमानत देने की मांग की है। समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नई दिल्ली। आतंकवादी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में आरोपित न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सरकारी गवाह बनने के आधार पर अमित चक्रवर्ती ने जमानत देने की मांग की है।

समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। पुलिस ने भी कहा कि अगर चक्रवर्ती को राहत दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। चक्रवर्ती हाल ही में सरकारी गवाह बन गए थे।

अब तक कोई आरोपपत्र दायर नहीं

चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि उन्हें निचली अदालत से मामले में माफी मिल चुकी है और वह जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। यह भी कहा कि वह तीन अक्टूबर 2023 से हिरासत में हैं और अब तक कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को पिछले साल तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अभी जेल में ही रहेंगे AAP नेता संजय सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। 31 जनवरी को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। संजय सिंह (Sanjay Singh) की तरफ से तर्क दिया गया था कि वह पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। 31 जनवरी को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

जमानत की मांग करते हुए संजय सिंह (Sanjay Singh) की तरफ से तर्क दिया गया था कि वह पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

वहीं, जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि सिंह 2021-22 की आबकारी घोटाला से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे। संजय सिंह को ईडी (ED) ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

विदेशों की जगह देश के शैक्षणिक संस्थानों में निवेश करें उद्योगपति: धनखड़

विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को देश के उद्योगपति मोटा-मोटा डोनेशन देते हैं। भारत से 50 मिलियन यूएस डॉलर का डोनेशन दिया जाता है। वक्त आ गया है कि यह डोनेशन भारत के शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाए। यह बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के इंदप्रस्थ महिला कॉलेज के 100वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

नई दिल्ली। विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को देश के उद्योगपति मोटा-मोटा डोनेशन देते हैं। भारत से 50 मिलियन यूएस डॉलर का डोनेशन दिया जाता है। वक्त आ गया है कि यह डोनेशन भारत के शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाए। खासकर लड़कियों को शिक्षित करने में इसे खर्च किया जाए। यह बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के इंदप्रस्थ महिला कॉलेज के 100वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

धनखड़ ने कहा कि वे विदेश में डोनेशन के खिलाफ नहीं है। लेकिन, सीएसआर फंड के लिए यह होना चाहिए। जिससे हमारे शैक्षणिक संस्थानों को और विकास हो सके। उन्होंने कहा, लड़कियों की शिक्षा क्रांति है। गणतंत्र दिवस पर सेना से लेकर, एयर फोर्स, हेलीकॉप्टर, पुलिस तक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। अब उनके और सशक्त बनने का समय है।

भारत को वर्ष 2047 में विकसित बनना है तो यह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही संभव होगा। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे नवाचार का जो विचार सोचें उसे कार्य रूप में परिणित करें। असफलता का डर उनके अंदर नहीं होना चाहिए। आप खुद के साथ समाज के उत्थान के लिए भी काम करें। अब वक्त बदल रहा है।

देश को एक वक्त अपना सोना गिरवीं रखना पड़ा था। अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर का है। हम आगे बढ़ रहे हैं और देश देख रहा है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2027-28 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। महिला आरक्षण बिल आ चुका है। जरूरी है कि उसके अनुरूप भागीदारी भी बढ़े।

उन्होंने कहा, देश को आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना होगा। खिलौने, चाकलेट, पतंग, फर्नीचर जैसी वस्तुएं बाहर से आना उचित नहीं लगता। सबका निर्माण हमारे यहां ही होना चाहिए। सुचेता कृपलानी और मीरा कुमार जैसे दिग्गज राजनेता आपके कॉलेज के छात्र रहे हैं। आप सभी के लिए यह गर्व की बात है।

इससे पहले कॉलेज के नए बनाए लोगों और 100 वर्ष की यात्रा पर आधारित काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर उपराष्टपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़, डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, कॉलेज के चयरेमैन आलोक बी. श्रीराम, प्राचार्य प्रो. पूनम कुमरिया आदि मौजूद रहे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिये दिखाई यात्रा

इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की शुरुआत 1904 में किनारी बाजार, चांदनी चौक की गली अनार में 'इंद्रप्रस्थ पुत्री पाठशाला' के रूप में हुई थी। कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला महिला कॉलेज है। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कॉलेज की वर्षों की गौरवशाली यात्रा को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में चार हजार से अधिक छात्राओं ने भाग लिया।

डीडीए का 8811 करोड़ रुपये का बजट पारित, इन परियोजनाओं पर रहेगा फोकस; जानिए दिल्ली को क्या-क्या मिलेगा

परिवहन विशेष न्यूज

उपराज्यपाल व डीडीए के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 8811 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। केंद्र सरकार के अनुरूप इसमें वार्षिक आवंटन का 61 प्रतिशत (लगभग) पूंजीगत व्यय शामिल है। मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने नागरिक सुविधाएं बेहतर करने गांवों का भी उन्नयन करने और दिल्ली के सुंदरीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए, DDA) के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 8,811 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। केंद्र सरकार के अनुरूप इसमें वार्षिक आवंटन का 61 प्रतिशत (लगभग) पूंजीगत व्यय शामिल है। इस बार बजट में मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, नागरिक सुविधाएं बेहतर करने, गांवों का भी उन्नयन करने और दिल्ली के सुंदरीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बोर्ड बैठक में सामने आया कि एलजी और अधिकारियों के नेतृत्व में बेहतर रणनीतियों के कारण, डीडीए की कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष के 4392 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ 7696 करोड़ रुपये हो गईं।

अगले वर्ष के अनुमानों में, डीडीए ने अपना राजस्व लक्ष्य 9182 करोड़ रुपये आंका है, जो चालू वर्ष से लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, डीडीए ने चालू वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियों पर 8804 करोड़ रुपये की राशि व्यय की, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत अधिक है, जबकि व्यय 5189 करोड़ रुपये था।

अगले वर्ष, डीडीए ने व्यय को चालू वर्ष के समान स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा है। नागरिक बुनियादी ढांचे पर रख-रखाव व्यय के आवंटन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कि 'दिवाली विशेष आवास योजना' की सफलता डीडीए के सामान्य विकास खाते (जीडीए) के बजट में दिखाई देती है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 के अनुसार 262 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2024-25 में 2145 करोड़ रुपये अधिशेष होने का अनुमान है। दस वर्ष बाद ऐसा पहली बार है जब डीडीए का जीडीए अधिशेष में होगा।

उपराज्यपाल ने डीडीए द्वारा प्राप्त किए जा रहे क्रमिक वित्तीय बदलाव का स्वागत किया और इस दिशा में प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों और उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू करेगा, जिनमें बेहतर आवास, लैंडस्केप के सौंदर्यीकरण और राजधानी के विरासत भवनों के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कुत्तों से परेशान महिलाओं ने थाली बजाकर जताया विरोध

वैशाली। आवारा कुत्तों से परेशान सेक्टर-1 स्थित नीलपदम कुंज सोसायटी की महिलाओं ने सोसायटी परिसर में थाली बजाकर अपना विरोध जताया। महिलाओं ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

विरोध जता रही महिलाओं ने कहा कि सोसायटी में दो वर्ष से लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। सोसायटी के ही कुछ लोग कुत्तों के लिए सोसायटी परिसर में खाना डालती हैं जिसकी वजह से आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। शिकायत पर रविवार को नगर निगम की टीम पहुंची थी लेकिन महज तीन कुत्ते ही पकड़ सकी जबकि अभी भी सोसायटी में करीब 24 से अधिक आवारा कुत्ते हैं, जिनके डर से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। अंजू गोस्वामी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक आवारा कुत्ते ने ढाई वर्ष के बच्चे पर हमला किया था। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। कुछ महिलाओं ने बताया कि पीएसी की एक दीवार सोसायटी से लगती है यह दीवार टूटी हुई इसके जरिये आवारा कुत्ते सोसायटी में प्रवेश कर जाते हैं। आरोप है कि आवारा कुत्तों को भगाने पर सोसायटी में रह रहे कुत्ता प्रेमी पीएफए सदस्यों का डर दिखाते हैं।

चलता रहेगा विरोध जब तक नहीं हटाए जाते कुत्ते

थाली पीट कर विरोध जताने वाली महिलाओं ने कहा कि जब तक सोसायटी परिसर से आवारा कुत्तों को नहीं हटाया जाता तब तक वह लोग अपना विरोध इसी तरह जताती रहेंगी। विभागीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाना चाहिए।

बुरी लत: मोबाइल छीनने पर खाना नहीं खाता बच्चा...

फर्श पर पटकता है सिर; एक से 3 साल तक के बच्चे आटिज्म के शिकार

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एक से तीन साल तक के बच्चे आटिज्म के शिकार हो रहे हैं। गाजियबाद के संयुक्त जिला अस्पताल में एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 665 बच्चों का पंजीकरण किया गया। यह सभी मोबाइल की लत से परेशान थे।

डॉक्टर साहब... मेरा तीन साल का बेटा दिनभर मोबाइल फोन में कार्टून देखता है। खाना खाते समय भी मोबाइल नहीं छोड़ता। अगर उसके हाथ से मोबाइल छीन लो तो खाना नहीं खाता और चिल्लाने लगता है। कई बार तो सिर फर्श पर पटकने लगता है।

जिला एमएमजी अस्पताल के मनोचिकित्सा प्रकोष्ठ में यह केस आदर्शनगर से आया। बच्चे में मोबाइल की लत लग जाने का यह अकेला मामला नहीं है। रोज ऐसे लगभग 150 मामले आ रहे हैं। आदर्शनगर के केस के बारे में अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विपिन चंद्र उपाध्याय ने बताया कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म की परेशानी हो गई है।

मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी पर ज्यादा समय बिताने पर यह परेशानी आती है। इसके शिकार बच्चों को दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत आने लगती है। वे बोलने में भी कतराने लगते हैं। इन बच्चों में आटिज्म नहीं होता, लेकिन उसके लक्षण आने लगते हैं।

एमएमजी के मनोचिकित्सा प्रकोष्ठ की क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. चंदा यादव का कहना है कि कई बार माता- को पिता भी व्यस्त होने के कारण या बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल का लालच देते हैं। यही लालच उनमें लत बन जाता है। इससे बच्चे के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और बच्चा जिद्दी हो जाता है।

ऐसे बच्चों में तनाव और इस एंग्जाइटी जैसे व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है, जो काफी चिंताजनक है। संयुक्त जिला अस्पताल में एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 665 बच्चों का पंजीकरण किया गया। यह सभी मोबाइल की लत से परेशान थे। इनमें से 515 की काउंसिलिंग कराई गई।

केस 1

मोबाइल लेने पर भाई के सिर पर मार दिया गिलास

एमएमजी अस्पताल में काउंसिलिंग कराने आई बोंझा निवासी महिला ने बताया कि उनका छह वर्षीय बेटा मोबाइल पर गेम खेलता रहता है तो शांत रहता है। मोबाइल लेते ही रोने और चीखने लगता है। एक दिन उसके हाथ से उसके बड़े भाई ने मोबाइल ले लिया तो गुस्से में उसने उसके सिर पर गिलास फेंक कर मार दिया। स्कूल शिक्षिका ने डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तब अस्पताल में ले गई। चार बार की काउंसिलिंग के बाद अब आदत में सुधार है।

केस-2

मोबाइल लेते ही चीजें फेंकने लगता है

संयुक्त अस्पताल में साथिया केंद्र पर काउंसिलिंग कराने पहुंची गोविंदपुरम की महिला ने बताया कि उनका 11 वर्षीय बेटा एक निजी स्कूल में छठीं कक्षा में पढ़ता है। स्कूल से आते ही वह मोबाइल पर गेम खेलने लगता है। खाने-पीने के लिए कहने पर गेम रुकते ही चीजें फेंकने लगता है। काउंसिलिंग चल रही है। अब स्कूल से आने के बाद पार्क में खेलने जाता है।

केस-3

देर रात तक गेम खेलता है, सुबह बताता है सिर में दर्द

एमएमजी अस्पताल में 12 वर्षीय बेटे का इलाज कराने पहुंचे विजय नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनका बेटा सुबह सिर में दर्द बताता है। डॉक्टर के पूछने पर पता चला कि देर रात तक मोबाइल पर रील्स देखता है। देर रात जागता रहता है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को कम से कम मोबाइल फोन दिया जाए। रात में जल्दी सुलाएं, नींद पूरी होने पर बिना दवाई के ही सिर दर्द बंद हो जाएगा।

तीन साल तक ज्यादा खतरा

बाल रोग विशेषज्ञ एवं प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि एक से तीन साल के बच्चों में मोबाइल आटिज्म का ज्यादा खतरा होता है। बच्चे जैसे ही बैठना और चलना शुरू करते हैं, अगर फोन के संपर्क में आ जाते हैं तो परेशानी आ जाती है। सवा साल से लेकर तीन साल की उम्र तक के बच्चों में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।

सर्दी में बढ़ जाती है परेशानी

संयुक्त अस्पताल में संचालित साथिया केंद्र के संचालक और काउंसलर मुकेश यादव ने बताया कि यह परेशानी सर्दी में अधिक बढ़ती है। रजाई या कंबल के अंदर बच्चे मोबाइल लेकर पूरी रात रील्स या वीडियो देखते रहते हैं, जबकि मां-बाप को लगता है उनका बच्चा सो रहा है। यह परेशानी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अधिक है।

इस तरह छुड़ाएं लत

घर के सदस्य एक साथ खाना खाएं

बच्चों के साथ समय दें, उन्हें किस्से- कहानियां सुनाएं।

सोने वाले कमरे से मोबाइल और टीवी दूर रखें।

बच्चा आनलाइन पढ़ाई करता है तो उन पर नजर रखें।

अजंतापुरम योजना में बनेंगे छह इंटर कॉलेज और छात्रावास

साहिबाबाद। अजंतापुरम योजना में छह इंटर कालेज और छात्रावास बनाए जाएंगे। योजना के लेआउट में इन्हें शामिल किया गया है। साथ ही यहां कई छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट के लिए जगह संरक्षित की गई है। आवास विकास परिषद ने योजना का लेआउट लगभग तैयार कर लिया है, जल्द ही स्वीकृति के लिए इसे लखनऊ भेजा जाएगा।

अजंतापुरम योजना करीब 342 एकड़ जमीन पर होगी। यहां 12 सहकारी समिति अपनी सोसायटी विकसित करेगी। यहां की सभी बड़ी सोसायटी में इंटर कालेज खोले जाएंगे। अब तक यहां छह इंटर कालेज की जमीन निश्चित की जा चुकी है। वहीं तीन छात्रावास बनाए जाने की योजना है। स्कूल और छात्रावास के लिए सभी समितियों को जगह देनी होगी। इसके साथ ही सभी सोसायटी को अपने यहां ऊर्जा निगम कार्यालय बनवाने होंगे। नर्सिंग होम के साथ ही अब जन औषधि केंद्र के लिए भी सोसायटियों को जमीन देनी होगी। अधिशासी अभियंता संजीव शुक्ला ने बताया कि लेआउट लगभग बनाया जा चुका है, स्वीकृति के लिए लखनऊ जल्द ही भेजा जाएगा। बिजली घर और स्कूल बनाने के लिए समितियों की जिम्मेदारी जमीन देने की है। सभी सोसायटी में ऊर्जा निगम के दफ्तर और जन औषधि केंद्र बनवानाअनिवार्य है। एक बड़ी सोसायटी जन विहार समिति के पदाधिकारी बीआर शर्मा ने बताया कि उनकी सोसायटी में एक 12वीं तक का स्कूल है। उनके अलावा पांच अन्य स्कूल भी बनवाए जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों के लिए भी जगह सोसायटियों में सुनिश्चित है।

इनसेट

एयरपोर्ट पर काम करने वालों के लिए बनाए जाएंगे पीजी होम

एयरपोर्ट करीब होने की वजह से आविप ने यहां हॉस्टल और पीजी होम बनाए जाने पर विशेष जोर दिया है। एयरहास्टेस के लिए अलग से पीजी होम बनाए जाने की योजना है। वहीं एयरपोर्ट होने की वजह से इस योजना में 10 से अधिक होटल के लिए जगह सुनिश्चित की गई है।

इनसेट

लखनऊ से मुहर लगते ही शुरू होगा काम

अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा ने बताया कि लेआउट लखनऊ भेजा जाएगा। लेआउट पर मुहर लगते ही योजना में काम शुरू करा दिया जाएगा। आवास आयुक्त ने 5 जनवरी को बैठक कर योजना जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए थे। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। योजना में सड़क, नाली खड़ंजा के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

दुकान के सामने ठेला खड़ा करने पर महिला ने बैट से की मारपीट, सब्जियां फेंकी...बीच सड़क पर हुआ हंगामा

पूछताछ में पता चला कि पूनम की दुकान के सामने ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में पूनम बैट लेकर सड़क पर आ गई और अंजू पर हमला करने लगी।

सोशल मीडिया पर एक महिला के हाथ में बैट लेकर लोगों से हाथापाई करने और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो नंदग्राम क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी महिला पूनम है। जिनकी परचून की दुकान है। उनकी दुकान के बाहर सब्जी का ठेला लगाने पर विवाद हुआ तो उन्होंने हंगामा कर ठेला पलट दिया।

एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लेकर जांच में वीडियो नंदग्राम क्षेत्र का निकला। घटना मंगलवार शाम की है। मामले में सब्जी का ठेला लगाने वाली अंजू नाम की महिला ने पूनम के खिलाफ तहरीर दी है।

पूछताछ में पता चला कि पूनम की दुकान के सामने ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में पूनम बैट लेकर सड़क पर आ गई और अंजू पर हमला करने लगी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कराया। आरोप है कि पूनम ने ठेला भी पलट दिया। मामले में अंजू ने पूनम के खिलाफ नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छोटे चौधरी का बड़ा खेला, इंडी गठबंधन की डूबती नाव से कूदने के लिए लगा है रेला

नीरज कुमार दुबे

विपक्षी गठबंधन की हालत से देश के सामने एक बात और स्पष्ट हो गयी है कि बेमेल विचारधारा वाला यह गठबंधन सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए बना था। जहां तक राष्ट्रीय लोक दल की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भाजपा के साथ आना तय हो चुका है।

विपक्ष के इंडी गठबंधन की नाव डूबती देख इस पर सवार राजनीतिक दलों में कूद कर अपनी जान बचाने की होड़ देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन की नाव को जिन नीतीश कुमार ने तैयार किया था वही सबसे पहले यहां से दूसरी तरफ कूद गये जिससे नाव का संतुलन गड़बड़ा गया। मौका देख ममता बनर्जी ने भी इस नाव से दूरी बना ली और अब राष्ट्रीय लोक दल भी इससे कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन की नाव से कूदने के लिए अपना सामान समेट रही है। इस गठबंधन में अब जो दल बचे हैं वह या तो आपस में ही लड़ रहे हैं या उन दलों के भीतर ही भितरघात देखने को मिल रही है जिसके चलते किसी का चुनाव चिह्न खतरे में पड़ गया है तो किसी की पार्टी का मालिकाना हक किसी और के पास चला गया है। विपक्ष की यह स्थिति देख अब प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिये गये संबोधन की वह बात किसी को अतिश्योक्ति नहीं लग रही कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में अकेले दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जायेगा।

विपक्षी गठबंधन की हालत से देश के सामने एक बात और स्पष्ट हो गयी है कि बेमेल विचारधारा वाला यह गठबंधन सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए बना था। जहां तक राष्ट्रीय लोक दल की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भाजपा के साथ आना तय हो चुका है। एकाध दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राष्ट्रीय लोक दल का भाजपा में विलय भी संभव है लेकिन अगर विलय नहीं हुआ तो गठबंधन होना पक्का है। हम आपको याद दिला दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन का प्रयास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी किया था लेकिन तब जयंत चौधरी ने साथ आने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय लोक दल 2014 से सभी चुनाव विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ा है लेकिन इसका उसे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन का रालोद को फायदा हुआ था साथ ही सपा कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा की सदस्यता भी मिल गयी थी।

लेकिन अब छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत चौधरी के पाला बदलने की अटकलों से विपक्षी खेमा बेचैन दिख रहा है। क्योंकि बात यह नहीं है कि छोटा दल गठबंधन से बाहर जा रहा है या बड़ा दल, बात यह है कि लंबे समय से गठबंधन में साथ रहा दल अब दूसरे के साथ जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि रालोद के लिए गठबंधन में सात लोकसभा सीटें दी गयी हैं। लेकिन यह सात सीटें कौन-सी होंगी इसका ऐलान नहीं किया गया था। इस बात से जयंत चौधरी नाराज बताये जा रहे थे। जयंत चौधरी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस से कुछ सीटें अपने लिये मांगी थीं लेकिन कांग्रेस की ओर से स्पष्ट इंकार कर दिये जाने के चलते उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इसलिए जब भाजपा की ओर से इस बार गठबंधन का प्रस्ताव आया तो उसे जयंत चौधरी मना नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ जाने पर जयंत चौधरी को मथुरा, कैराना, अमरोहा और बागपत सीटें मिल सकती हैं। अभी इनमें से अमरोहा को छोड़कर बाकी तीनों सीटें भाजपा के पास हैं। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के क्षेत्रीय दल के दर्जे को बचाना है। यदि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन लोकसभा चुनावों में मत हासिल नहीं किये तो संभव है कि उनका चुनाव चिह्न नल भी छिन जाये। जयंत चौधरी यह बात समझ रहे हैं कि भले समाजवादी पार्टी उन्हें लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दे दे लेकिन सीटें जीतने की ज्यादा संभावना भाजपा के साथ मिलकर लड़ने में ही है।

दूसरी ओर भाजपा भी यह समझ रही है कि किसान आंदोलन के दौरान से नाराज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को पूरी तरह तभी साधा जा सकता है जब राष्ट्रीय लोकदल साथ आ जाये। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी नुकसान पश्चिमी क्षेत्र में ही हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप नहीं था इसलिए भाजपा 2024 में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। भाजपा का प्रयास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल की जाये और इसके लिए तमाम प्रयास किये भी जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चा सामने आई कि जयंत चौधरी ने पांच से सात लोकसभा सीटों की मांग रखी थी लेकिन भाजपा की ओर से चार सीटों का ही वादा किया गया है। भाजपा को पता है कि यदि जयंत को ज्यादा सीटें दी गयीं तो उत्तर प्रदेश की अन्य सहयोगी पार्टियां अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी भी ज्यादा सीटें मांगेंगी। बताया जा रहा है कि गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में भी एक पद मिल सकता है।

इस तरह की भी चर्चा है कि जयंत चौधरी की पार्टी 12 फरवरी से पहले भाजपा के साथ आ सकती है और जब 12 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे तो जयंत चौधरी भी साथ होंगे। हम आपको बता दें कि नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर से पार्टी के एक महीने के ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मोदी सरकार के जन-कल्याणकारी कदमों को रेखांकित करने के अलावा चुनाव घोषणापत्र के लिए किसानों और मजदूरों सहित ग्रामीण आबादी से सुझाव मांगेंगे। पार्टी के सदस्य लोगों से संवाद के दौरान गांवों में गायों और कृषि उपकरणों की पूजा भी करेंगे। देखा जाये तो नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मुजफ्फरनगर का चयन कर बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है क्योंकि यह क्षेत्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का केंद्र था। हालांकि बाद में केंद्र ने उन कानूनों को वापस ले लिया था लेकिन आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है।

बहरहाल, जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ और घटक या उन घटकों के बड़े नेता सत्तारुढ़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं क्योंकि देश के राजनीतिक मिजाज से सभी वाकिफ हैं। सभी इस बात को समझ रहे हैं कि देश की ताजा राजनीतिक स्थिति यही है कि दस साल के शासन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने की बजाय देश-विदेश में और बढ़ी ही है।

> अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि रालोद के लिए गठबंधन में सात लोकसभा सीटें दी गयी हैं। लेकिन यह सात सीटें कौन-सी होंगी इसका ऐलान नहीं किया गया था। इस बात से जयंत चौधरी नाराज बताये जा रहे थे। जयंत चौधरी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस से कुछ सीटें अपने लिये मांगी थीं लेकिन कांग्रेस की ओर से स्पष्ट इंकार कर दिये जाने के चलते उन्हें निराशा हाथ लगी थी।

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा हायराइडर को मिलेगा 7-सीटर वर्जन, जानिए डिटेल्स

Hyundai Alcazar MG Hector Plus Tata Safari और Mahindra XUV700 को टक्कर देते हुए Maruti Suzuki अपनी Grand Vitara 7-सीटर के साथ इन 7-सीटर एसयूवी के लिए एक नो-नॉनसेंस विकल्प पेश करने का लक्ष्य बना रही है। आंतरिक रूप से कोडनेम Y-17 7-सीटर एसयूवी एक टोयोटा अर्बन क्रूजर हैराइडर-आधारित समकक्ष को भी जन्म देगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड (MSIL) के पास वर्तमान में Grand Vitara के साथ मध्यम आकार के एसयूवी सेगमेंट पर अच्छी पकड़ है। यहां तक कि इसकी सिब्लिंग Toyota Urban Cruiser Hyryder भी अच्छी संख्या में बिक रही है।

हालांकि, 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट अभी भी भारतीय कार निर्माता द्वारा अप्रयुक्त है और हम निकट भविष्य में एक नया मॉडल देख सकते हैं। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

Grand Vitara के 7-सीटर वेरिएंट में क्या खास?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रैंड विटारा के 7-सीटर संस्करण पर काम चल रहा है और वर्ष 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बाद टोयोटा हायरडर 7-सीटर की शुरुआत होगी।

Hyundai Alcazar, MG Hector Plus, Tata Safari और Mahindra XUV700 को टक्कर देते हुए, Maruti Suzuki अपनी Grand Vitara 7-सीटर के साथ इन 7-सीटर एसयूवी के लिए एक नो-नॉनसेंस विकल्प पेश करने का लक्ष्य बना रही है। आंतरिक रूप से कोडनेम Y-17, 7-सीटर एसयूवी एक टोयोटा अर्बन क्रूजर हैराइडर-आधारित समकक्ष को भी जन्म देगी।

तीन-पंक्ति वाली एसयूवी को परिचित वैश्विक सी प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाएगा। हालांकि, सीटों की एक अतिरिक्त पंक्ति को समायोजित करने के लिए व्हीलबेस लंबा होने की संभावना है।

इंजन

हुड के तहत, इसे 1.5-लीटर K15C पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन की वर्तमान फसल 7-सीटर ग्रैंड विटारा और हाइडर के पैकेज का हिस्सा बनी रहेगी। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ आएगा।

स्टाइल और डिजाइन एलीमेंट

जहां तक स्टाइल की बात है, मामला कमोबेश वैसा ही रहेगा, हालांकि हम 7-सीटर ग्रैंड विटारा के लिए कुछ नए स्टैंड-आउट डिज़ाइन एलीमेंट की उम्मीद करते हैं। सड़क उपस्थिति के मामले में, यह निश्चित रूप से मौजूदा 5-सीटर समकक्ष से आगे होगी।

यदि कुछ मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो ग्रैंड विटारा और हायराइडर 7-सीटर संस्करण का निर्माण मारुति सुजुकी की नई खरखौदा, हरियाणा स्थित फैसिलिटी में किया जाएगा। ये नया प्लांट साल 2025 तक तैयार हो जाएगा और 7-सीटर एसयूवी असेंबली लाइन से निकलने वाली पहली कार होगी।

कार इंश्योरेंस प्रीमियम को करना चाहते हैं कम, तो किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

कार खरीदने के बाद हर साल इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हुए कुछ लोग ज्यादा प्रीमियम भरते हैं। किन बातों का ध्यान रखने से प्रीमियम कम करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं।

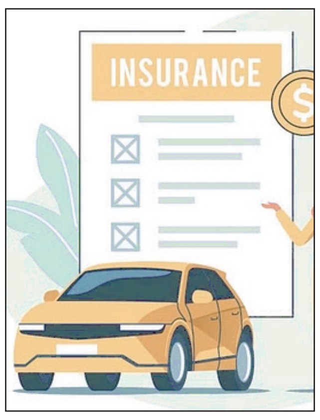

दुनियाभर में बड़ी संख्या में कार का उपयोग किया जाता है। कार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस भी करवाना काफी जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण वह रिन्यू करवाते हुए ज्यादा प्रीमियम देते हैं। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किन बातों का ध्यान रखते हुए प्रीमियम कम किया जा सकता है।

जरूरी है इंश्योरेंस

कार के लिए इंश्योरेंस काफी जरूरी होता है। वैलिड इंश्योरेंस होने के कई फायदे मिलते हैं। जिनमें कार चोरी होने से लेकर हादसा होने तक कार मालिक को बिना परेशानी पैसे मिलते हैं। इसके अलावा भारत में इंश्योरेंस वैलिड न होने पर पुलिस की ओर से चालान भी काटा जा सकता है।

कार चलाते हुए रखें ध्यान

जब भी कार चलाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। कार को तेज गति में नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने से कार को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है और इसका फायदा यह होता है कि कार के लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना पड़ता। क्लेम न लेने के कारण पॉलिसी रिन्यू करवाते हुए एनसीबी मिलती है। हर साल यह बढ़ती है जिससे प्रीमियम में छूट मिलती है।

सेफ्टी फीचर्स से होगा फायदा

कार में अगर अलग से सेफ्टी फीचर्स लगवाएं तो इसका फायदा प्रीमियम में मिलता है। अगर कार में सामान्य से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं तो इससे कार चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दी जाती है तो पॉलिसी रिन्यू करवाते हुए प्रीमियम में छूट पाई जा सकती है।

मोडिफिकेशन से नुकसान

अगर आप भी अन्य कारों की तुलना में अपनी कार को अलग दिखाना चाहते हैं। तो कुछ लोग कार मोडिफाई करवाते हैं। लेकिन ऐसा करने से न सिर्फ कार में अतिरिक्त भार जुड़ता है। वहीं इससे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कार को उसी तरह रखें जिस तरह कंपनी की ओर से बनाई जाती है। इससे प्रीमियम में दिए जाने वाले अतिरिक्त पैसे को बचाया जा सकता है।

काइनेटिक ई लूना भारतीय बाजार में 70 हजार रुपये की कीमत पर लॉन्च, जानिए फीचर्स और खासियत

Kinetic E-Luna कलर्ड डुअल-ट्यूबलर स्टील चेसिस पर आधारित है और इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। इस इलेक्ट्रिक मोपेड को पावर देने वाला 2.0 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक है जो प्रति चार्ज 110 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है। All New E-Luna के लिए बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है और डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Kinetic Green ने पॉपुलर लूना मोपेड को इलेक्ट्रिक अवतार में पेश कर दिया है। कंपनी ने E-Luna की एक्स-शोरूम कीमत 70,000 रुपये रखी है। इस ईवी के लिए बुकिंग गणतंत्र दिवस से ही 500 रुपये के मामूली टोकन अमाउंट पर शुरू हो गई थी।

काइनेटिक ग्रीन के फाउंडर और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी के अनुसार, कंपनी को तब से 40,000 से अधिक ग्राहकों की रुचि प्राप्त हुई है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

Kinetic E-Luna कलर्ड, डुअल-ट्यूबलर स्टील चेसिस पर आधारित है और इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। इस इलेक्ट्रिक मोपेड को पावर देने वाला 2.0 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक है, जो प्रति चार्ज 110 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है।

बाद में कंपनी की योजना 1.7 kWh और बड़ा 3.0 kWh बैटरी पैक वेरिएंट भी पेश करने की है। इसे 2.2 किलोवाट मोटर द्वारा संचालित किया जाता है, जो इसे 50 किमी प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त करने में मदद करता है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इसमें पूरी तरह से डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साइड-स्टैंड सेंसर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और जरूरी सामान ले जाने के लिए सुविधाजनक बैग हुक हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी अलग करने योग्य पिछली सीट व्यावहारिकता जोड़ती है।

कलर ऑप्शन और बुकिंग डिटेल्स

All New E-Luna के लिए बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है और डिलीवरी जल्द ही देश भर के सभी काइनेटिक ग्रीन डीलरशिप से शुरू होने वाली है। इसके अतिरिक्त, मॉडल अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगा। इस मॉडल को आप 5 कलर ऑप्शन- Mulberry Red, Ocean Blue, Pearl Yellow, Sparkling Green और Night Star Black में खरीद सकते हैं।

Yamaha FZ-X Chrome edition 1.40 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च, पहले 100 कस्टमर्स को मिलेगा ये खास ऑफर

Yamaha ने FZ-X को आकर्षक क्रोम कलर स्कीम में लॉन्च किया है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये रखी गई है। जापानी दोपहिया निर्माता के ओर से शुरुआतीक ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर दिया दा जा रहा है। इसके क्रोम वैरिएंट के लिए पहली 100 ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को वाहन डिलीवरी पर कैसियो जी-शॉक घड़ी मिलेगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Yamaha ने FZ-X को आकर्षक क्रोम कलर स्कीम में लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये रखी गई है। इस मॉडल को हाल ही में संपन्न भारत मोबिलिटी शो 2024 में प्रदर्शित किया गया था। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

पहले 100 कस्टमर्स को मिलेगा ये ऑफर

जापानी दोपहिया निर्माता के ओर से शुरुआतीक ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर दिया दा जा रहा है। इसके क्रोम वैरिएंट के लिए पहली 100 ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को वाहन डिलीवरी पर कैसियो जी-शॉक घड़ी मिलेगी।

नई कलर स्कीम के अलावा, मोटरसाइकिल डिजाइन, फीचर्स और आयामों के मामले में अपरिवर्तित है।

इंजन डिटेल

इस मॉडल को पावर देने वाला वही 149 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 12.4 एचपी और 13.3 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। ये मोटर पांच-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। ये मॉडल E20 फ्यूल के साथ भी कम्पेटिबल है।

फीचर्स

FZ-X में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), रियर डिस्क ब्रेक के साथ फ्रंट में सिंगल-चैनल ABS, मल्टी-फंक्शन पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राउंड एलईडी हेडलाइट, रियर मडगार्ड सहित अपनी मौजूदा विशेषताएं मौजूद हैं। अन्य सुविधाओं के बीच लोअर इंजन गार्ड और ब्लूटूथ-सक्षम वाई-कनेक्ट ऐप भी दिया गया है।

स्पेसिफिकेशन

सस्पेंशन ड्यूटी के लिए, मोटरसाइकिल में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस यूनिट मिलती है। ब्रेकिंग के लिए इसमें ABS के साथ 282 मिमी फ्रंट डिस्क और रियर व्हील पर 220 मिमी डिस्क लगी है।

2024 Pulsar N150 और N160 नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ हुई लॉन्च, जानिए प्राइस

Bajaj Auto ने अपनी पॉपुलर बाइक्स Pulsar N150 और N160 के 2024 वर्जन लॉन्च किए हैं। इसे परिचित डिजाइन और परफॉरमेंस को बरकरार रखते हुए कुछ स्वागत योग्य टेक्निकल अपडेट मिले हैं। दोनों मोटरसाइकिलों के बेस-स्पेक मॉडल अपरिवर्तित हैं टॉप-स्पेक वेरिएंट में नए पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रूप में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड की सुविधा है। इसके अलावा दोनों का डिजाइन परफॉरमेंस और डायमेंशन समान हैं।

नई दिल्ली। Bajaj Auto ने अपनी पॉपुलर बाइक्स Pulsar N150 और N160 के 2024 वर्जन लॉन्च किए हैं। इसे परिचित डिजाइन और परफॉरमेंस को बरकरार रखते हुए कुछ स्वागत योग्य टेक्निकल अपडेट मिले हैं। अपडेटेड मोटरसाइकिलों के दो वेरिएंट होंगे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत N150 के लिए 1.18 लाख रुपये और N160 के लिए 1.30 लाख रुपये से शुरू होगी। दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

2024 Pulsar N150 और N160 में क्या नया?

दोनों मोटरसाइकिलों के बेस-स्पेक मॉडल अपरिवर्तित हैं, टॉप-स्पेक वेरिएंट में नए, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रूप में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड की सुविधा है। इसके अलावा दोनों का डिजाइन, परफॉरमेंस और डायमेंशन समान हैं।

नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम में फ्यूल एफिशियंशी, औसत माइलेज और डिस्टेंस-टू-एम्पटी डेटा दिखाता है। इसके अलावा बजाज राइड कनेक्ट ऐप के माध्यम से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, राइडर आसानी से इनकमिंग कॉल और नॉटिफिकेशन अलर्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा, N150 में अब सिंगल-चैनल ABS के साथ रियर डिस्क ब्रेक मिलता है।

इंजन

N150 अपनी 149.5 cc, सिंगल-सिलेंडर मोटर के साथ जारी है, जो 14.5 hp और 13.5 Nm उत्पन्न करता है। वहीं, N160 अपनी 165 cc यूनिट को बरकरार रखती है, जो 17 hp और 14.3 Nm उत्पन्न करता है।

2024 Bajaj Pulsar N150 और N160 की कीमतें

मॉडलों के 2024 संस्करणों में प्रत्येक के दो संस्करण हैं। N150 की कीमत क्रमशः 1.18 लाख रुपये और 1.24 लाख रुपये है। इसी तरह, N160 दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 1.31 लाख रुपये और 1.33 लाख रुपये है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

न्याय प्रणाली में सुधार कैसे हो?

डा. वरिंदर भाटिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय प्रणाली को अधिक लचीला और अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि न्याय प्रदान करने वाली कानूनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने की जरूरत है...

विधि आयोग की सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए छुट्टियों के दिनों में कटौती की जानी चाहिए। अमरीकी विचारक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था, 'न्यायपालिका राज्य का सबसे कमजोर तंत्र होता है, क्योंकि उसके पास न तो धन होता है और न ही हथियार। धन के लिए न्यायपालिका को सरकार पर आश्रित रहना होता है और अपने दिए गए फैसलों को लागू कराने के लिए उसे कार्यपालिका पर निर्भर रहना होता है।' ऐसे कई मामले हैं जिन्हें केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय प्रणाली को अधिक लचीला और अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि न्याय प्रदान करने वाली कानूनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। वैसे तो हमारी न्याय प्रणाली दुनिया के अनेक देशों से बेहतर है, फिर भी इसमें रचनात्मक सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जो अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई थी। देश में कई स्तर की अदालतें मिलकर न्यायपालिका बनाती हैं। भारत की शीर्ष अदालत नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है और उसके तहत विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के मातहत जिला अदालतें और उनकी अधीनस्थ अदालतें हैं जिन्हें निचली अदालतें कहा जाता है। इनके अलावा ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतें आदि मिलकर न्यायपालिका की रचना करते हैं। भारत में संविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों अंगों विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक समान शक्तियां दी हैं। एक समान शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) को ही संविधान का संरक्षक कहा गया है। न्याय की बात जहां आती है, वहां कुछ बड़ी सैद्धांतिक बातें सामने आने लगती हैं। मसलन न्याय में विलंब अन्याय है, वादकारी का हित सर्वोच्च है, इत्यादि, पर जब व्यवहार में हम देखते हैं तो ठीक इसके विपरीत नजर आता है। प्रक्रियात्मक खामियों के अलावा सिस्टम में व्याप्त कदाचार, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के साथ कुटिलता से किसी मामले को अनंत काल तक लटकाए रखने एवं न्याय में विलंब होने और 'तारीख पर तारीख' की त्रासदी सामने आती है। बॉलीवुड स्टार सन्नी दियोल का मशहूर फिल्मी डायलॉग 'तारीख पर तारीख' अब रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया है।

यह कटु सत्य है कि न्याय प्रणाली की कुछ कमियों के चलते अनेक वादकारियों को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण कई बार न तो समय से न्याय मिल पा रहा है, न ही उनकी पीड़ा का कोई तारणहार है। वे न्याय प्रणाली के अंतिम पायदान पर असहाय पड़े रहने के लिए अभिशप्त हैं। यही कारण है कि समाज में मौके पर ही न्याय की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में घटित हो रही है। इसे क्या न्याय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है? तारीख पर तारीख के कई कारण विदित हैं, जैसे कि बार (वकील) और बेंच (अदालतें) न्यायिक प्रक्रिया के मूल आधार हैं। अदालतों में मुकदमों का अंबार लगने का सबसे बड़ा कारण है धीमी सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तुलना में निचली और जिला अदालतों की हालत ज्यादा खराब है। मुकदमों की शुरुआत यहीं से होती है और जिस मात्रा में मुकदमे दायर होते हैं, उस अनुपात में निपटारा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कई बार समयबद्ध सुनवाई करने का आदेश देते भी हैं, लेकिन जजों की कमी भी सुनवाई को प्रभावित करती है। पुलिस के पास साक्ष्यों के वैज्ञानिक संग्रहण हेतु प्रशिक्षण का अभाव है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी प्रायः अपने कत्र्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं जिससे सुनवाई में अत्यधिक विलंब हो जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध भी बना रहता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने का काम अभी भी अधर में ही लटका हुआ है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रशासनिक एजेंसियां बेहतर प्रदर्शन नहीं करती और न्यायिक प्रणाली की गति बहुत धीमी है। इसकी मुख्य वजह अदालत में मामलों की बेतहाशा बढ़ती संख्या और कार्यवाही में होने वाली देरी है।

वैसे तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट, प्रति व्यक्ति न्यायाधीशों की संख्या अत्यंत सीमित होने के कारण मुकदमों के निस्तारण में विलंब होता है, पर निचली अदालत में वादकारियों को न्याय मिलने में अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वे प्रणालीगत उत्पीडऩ के शिकार बनकर रह जाते हैं। उनका इतना अधिक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण होता है कि आम तौर पर लोग पुलिस, अदालत जाने के नाम से ही घबराने लगते हैं। साथ ही कुछ लोगों में कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढऩे लगती है। अनेक लोगों का सत्र न्यायालय में या निचली अदालतों में यह अनुभव बड़ा ही कड़वा और पीड़ादायक होता है। यहां पर प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार न्याय प्रणाली को अनुकूल बनाने की कवायद और भी जरूरी लगती है। न्याय प्रणाली को लचीला और अनुकूल बनाने की दिशा में इस समय आईटी सेक्टर प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की वजह से न्यायिक प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने न्यायिक प्रणाली को आसान कर दिया है। आम लोगों के लिए न्यायिक प्रणाली अब सुलभ हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सिस्टम को आम लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया है। ऑनलाइन सिस्टम से काम करने में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम लगभग सभी निर्णयों तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे लिए और आभासी प्रणाली के साथ उपलब्ध हैं। इस समय कानूनी प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि हम न्याय तक पहुंच की बात करते हैं, तो अंततः प्रचलित भाषा को किसी अन्य भाषा का स्थान लेना होगा। न्यायिक सुधारों को लेकर विधि आयोग ने कई सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी हैं, जिनमें कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, लेकिन इस दिशा में कोई गंभीर पहल अब तक नहीं हो पाई है।

विधि आयोग ने अपनी हर सिफारिश में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की कमी को पूरा करने का सुझाव दिया है। आज न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अदालतों में मुकदमों के बोझ को कम करना। यह तभी संभव होगा जब न्यायालयों में कार्य अवधि की सीमा बढ़ेगी। जिन राज्यों में मुकदमों का बोझ अधिक है, वहां विशेष अदालतें गठित करने का भी सुझाव दिया गया है। उच्च न्यायालय का विकेंद्रीकरण, यानी सभी राज्यों में इसकी खंडपीठ का गठन किया जाए, ताकि मुकदमों के निस्तारण में तेजी आए। विधि आयोग की सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए छुट्टियों के दिनों में कटौती की जानी चाहिए। अमरीकी विचारक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था, 'न्यायपालिका राज्य का सबसे कमजोर तंत्र होता है, क्योंकि उसके पास न तो धन होता है और न ही हथियार। धन के लिए न्यायपालिका को सरकार पर आश्रित रहना होता है और अपने दिए गए फैसलों को लागू कराने के लिए उसे कार्यपालिका पर निर्भर रहना होता है।' जब भी हम न्याय तक पहुंच या कानूनी प्रणाली के कामकाज की बात करते हैं तो हम हमेशा अदालती मामलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिन्हें केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि छोटे-छोटे मामलों को मिल-बैठ कर सुलझा लिया जाए और अदालतों को बोझिल होने से बचा लिया जाए?

संपादक की कलम से

लोकतंत्र की हत्या का चुनाव

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधलेबाजी पर देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी सामने आई है कि यह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। निर्वाचन अधिकारी पर मुकदमा चलाकर सजा दी जानी चाहिए। यह साफ देखा जा सकता है कि निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों को 'विकृत' कर रहे हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हम यह देखकर हैरान हैं।' जस्टिस चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी पराकाष्ठा की है। अलबत्ता वह बेहद संयम के साथ अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। इस प्रकरण में सवाल और संदेह तत्कालीन राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की भूमिकाओं पर भी हैं। पुरोहित ने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर इस कलंक से बचने का प्रयास किया है। उच्च न्यायालय इस मामले में 'अंतरिम आदेश' दे सकता था। उसमें वह असफल रहा। यह टिप्पणी भी प्रधान न्यायाधीश की है। चुनाव आयोग की बुनियादी जिम्मेदारी ही देश भर में निष्पक्ष चुनाव कराने की है। उसकी क्षमताओं और चुनाव प्रबंधन का डंका विश्व भर में बजता रहा है। कई देश हमारे चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए आमंत्रित भी करते रहे हैं, लेकिन एक मेयर के चुनाव में ऐसी कलंकित धांधलेबाजी सामने आई है। खुद चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर सर्वोच्च अदालत तक याचिका देने की नौबत ही क्यों आई? बहरहाल अब मामला सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है, तो संभव है कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव दोबारा कराया जाए।

प्रधान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास मेयर चुनाव से जुड़े तमाम दस्तावेज जमा कराने के आदेश दिए हैं। मतपत्र-वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए कहा है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया का वीडियो पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ नगर निगम में 'आप' और कांग्रेस के 20 पार्षद हैं और भाजपा के 16 पार्षद हैं। हमने दो टीवी चैनलों पर उस मौलिक, असंपादित फुटेज का प्रसारण देखा है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह मतपत्रों पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतपत्रों पर दाहिनी तरफ पेन से कुछ निशान भी बना रहे हैं। उन आठ मतपत्रों को ही बाद में 'अवैध' करार दिया गया, नतीजतन भाजपा का मेयर बहुमत न होने के बावजूद 'विजेता' घोषित कर दिया गया। 'आप'-कांग्रेस के 40 फीसदी वोट एकसाथ ही अवैध करार दिए गए, यह अभूतपूर्व, आश्चर्यजनक निर्वाचन रहा। वैसे 2016 में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव थे। उसमें विपक्ष के 12 वोट अवैध करार दिए गए, क्योंकि उन पर अलग पेन और स्याही का इस्तेमाल किया गया था। यह लोकतंत्र की बदकिस्मती है कि अब भी ऐसी बेशर्म धांधलियां की जा रही हैं। बहरहाल चैनलों पर दिखाए गए फुटेज में निर्वाचन अधिकारी बार-बार सीसीटीवी कैमरे की ओर देख रहे हैं। अदालत ने भी संशय व्यक्त किया है कि निर्वाचन अधिकारी कैमरे की ओर बार-बार क्यों देख रहे हैं? वह भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं? अब उन पर सुप्रीम अदालत की निगाह है। दरअसल चुनाव में यह धांधली एक पूरा षड्यंत्र लगता है, क्योंकि सदन में कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, जो कैमरे की दिशा बदलने के संकेत कर रहे हैं। कुछ गालियां भी दे रहे हैं। अनिल मसीह चंडीगढ़ भाजपा के एक प्रकोष्ठ में महासचिव रहे हैं। सवाल तो यही है कि उन्हें यह दायित्व क्यों सौंपा गया?

राय

चुनाव के खिलौने

हिमाचल में भी राजनीतिक खिलौने सज-धज कर निकल रहे हैं ताकि जनता के सामने कुछ करतब दिखाए जाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में अयोध्या नगरी के तार अंब-अंदौरा तक जुड़े, तो ऊना से ही वृंदावन चलने के लिए स्पेशल बस ने हामी भरी। यकायक आस्था के प्रसार में सरकारों की हरी झंडियां और यात्रीगण खिलौने ही तो बनेंगे। कभी ओलंपिक जीतकर एक आध पदक जब हमारे हिस्से आता था, तो हम राष्ट्र की भावना में तिरंगा उठाते थे, बिना कहे, बिना प्रचारित। अब दुनिया बदल गई और सियासत में सत्ता का प्रदर्शन नित नए प्रचार सामग्री में हमें खिलौना बना सकती है। लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में जनता के साथ खिलौना-खिलौना खेलने की कई पारियां और राजनीतिक समाधानों की तैयारियों में हिमाचल भी शरीक हो रहा है। कुछ काजल लगाए आंखें दिखा रहे, तो कुछ की आंखों से काजल बह रहा है। चुनाव का भी काजल होता है, इसलिए सुरमेदानियों में बवाल है। धर्मशाला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गर्जना में चुनाव के टिकट, उस भीड़ में कहीं अग्रणी होते देखे गए, तो कहीं नेताओं के झुंड में पार्टी की संभावनाएं आकाश को देखती रहीं। कांग्रेस ने भी ताज पहनने की मुद्रा में हिमाचल के प्रयोग दिल्ली में करने शुरू किए, तो आवाज आई कि राज्य की सत्ता को अब चुनाव के लिए कुछ खिलौने चाहिएं। ये खिलौने पहले राज्य की सत्ता के लिए बड़ी मशक्कत से कांग्रेस को मजबूत करते रहे और अब सूचना है कि विधानसभा तक पहुंचे कुछ कांग्रेसी विधायक सीधे केंद्र भेजे जाएंगे। कितना आसान है किसी विधायक को ही लोकसभा चुनाव में आजमाना। कितना बड़ा हो जाता है खिलौना जब उसे बार-बार उछाला जाए। ऐसे में कांग्रेस की सूची में विधायकों की मंडी से निकलेंगे लोकसभा चुनाव के खिलौने। यानी कुल मिलाकर गठजोड़ यह कि मंडी के लिए प्रतिभा सिंह के अलावा विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से इंद्रजीत लखनपाल या मुकेश अग्निहोत्री, कांगड़ा से आरएस बाली या सुधीर शर्मा तथा शिमला संसदीय सीट के लिए विनय कुमार या विनोद सुल्तानपुरी के नाम कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खोज है। जाहिर है इन चेहरों के पीछे कांग्रेस की सियासत व रियासत का हिसाब किताब है। हम चुने हुए विधायकों को अगले चुनाव की जिम्मेदारी तो दे ही सकते हैं और यह कांग्रेस का नया अवतार है, जो मोदी सरकार के मुकाबले में अपना मानव संसाधन विकसित कर रहा है। जनता वही होगी जिसने एक साल पूर्व अपने जमा व घटाव में कांग्रेस को सत्ता और भाजपा को सत्ताच्युत किया था। अब पुनः इसी से पूछा जाएगा, तेरा मूड क्या है। यानी जनता फिर से खिलौना बनी सोचती रहेगी कि इस बार लोकतंत्र में उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाए। उसके लिए भी चुनाव खिलौने से न तो ऊपर और न ही बेहतर है। यही वजह कि जनता के सामने राजनीतिक प्रदर्शन अब अपने चरम को तलाश रहा है। शायद अयोध्या के रास्ते पर मिल जाए, इसलिए ट्रेनें 'आस्था एक्सप्रेस' के नाम पर चलने लगीं। हर बार एक नए अनुभव में चुनाव की बिसात और खिलौनों की जमात में शिरकत करते राजनीतिक हौसलों की अद्भुत निशानियां। हमारे इर्द-गिर्द हाल ही में खड़ा हुआ केंद्रीय बजट जो दे गया, उसी के अक्स में हिमाचल के बजट के लंबे आलेख। छोटे से पर्वतीय राज्य के वित्तीय उद्गार एक चुनाव के सामने कितना सीना दिखाते हैं, यह आने वाले विधानसभा सत्र की खूबी में दर्ज होगा। दर्ज होगा कि हिमाचल कितना कर्ज उठाता है और अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में बांट देता है। पिछले साल के सपनों में और कितना काजल लगा पाता है, ताकि जनता कह उठे, 'वाह! कांग्रेस सरकार, वाह!' आपदा के वीभत्स अध्यायों से बाहर निकल कर हिमाचल सरकार के सामने केंद्र के काले चिट्ठे उन मनहूस राहों में, जहां मोदी सरकार के हाथ मदद नहीं दे पाए। ओपीएस के मुद्दे पर आई राज्य सरकार का केंद्र से टकराव एनपीएस के फंड पर अब 'चुनाव-चुनाव' करेगा, तो अपनी ताकत के लिए ऐसी शुभ सूचनाएं लिखेगा, जो जनता को प्यारी-हितकारी लगेंगी।

साइबर सुरक्षा : चुनौतियां और समाधान

साइबर अपराध से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की साइबर अपराध घटना होती है तो 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने भी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षित भारत पहल जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साइबर सिक्योरिटी के गंभीर खतरों को देखते हुए जरूरत है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाए। बच्चों को भी साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समान रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके जागरूक किया जाए'

21वीं सदी को हम सूचना और क्रांति के युग (इनफार्मेशन एज) से जानते हैं। सूचना और क्रांति से मानव जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आया है। मुख्य रूप से संचार के नए-नए साधनों ने पूरे विश्व को ही एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्स एप्प, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ईमेल इत्यादि ने मीलों की दूरियों को खत्म कर दिया है, लेकिन जिस तरह से हम पिछले एक दशक में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम में भी वृद्धि हुई है। साइबर हमलों से भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत में हमें साइबर क्राइम का सबसे खतरनाक रूप कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिला। 2020-21 में जहां भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तो दूसरी ओर साइबर अटैक्स से। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के समय एशिया महाद्वीप में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स झेलने पड़े। ये साइबर अटैक्स सबसे ज्यादा वित्तीय, बीमा और उन संस्थाओं पर किए गए जो महामारी में लोगों को एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रही थीं। अभी हाल में ही एक अमरीकी कंपनी ने दावा किया है कि भारतीयों का डाटा डार्क वेब पर उपलब्ध है, जो कि वास्तव में ही एक गंभीर और सोचनीय विषय है। अपराधी इस डाटा, जिसमें पब्लिक के फोन नंबर से लेकर आधार तक की जानकारी शामिल है, को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पिछले महीने ही दिल्ली पुलिस ने डार्क वेब पर भारतीय नागरिकों का डाटा बेचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। भारत में स्मार्टफोन आने से एक बहुत बड़ा वर्ग इंटरनेट से जुड़ गया है।

वर्तमान में भारत की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आज हम देखते हैं कि एक गरीब से गरीब आदमी भी स्मार्टफोन यूज करता है। इंटरनेट ने लोगों के बीच सूचना प्रसार में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाकर डिजिटल डिवीजन को खत्म करने का काम किया है। इसके अलावा सरकारों को भी अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और प्रसार करने में आसानी हुई है। इसके अतिरिक्त सिटीजन जर्नलिज्म व डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जैसी चीजें भी इंटरनेट से ही संभव हो पाई हैं। एक अनुमान के अनुसार

भारत में चीन के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। लगभग 1.05 बिलियन यूजर्स के साथ चीन वैश्विक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में सबसे आगे है। चीन में लगभग 4 में से 3 लोग (74.36 फीसदी) इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग करने वाली अपनी आधी आबादी (49.15 फीसदी) के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी करीब-करीब भारत में 692 मिलियन लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जोकि एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक यह संख्या बढक़र 900 मिलियन होने की उम्मीद है। लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव एवं डिजिटल अज्ञानता के कारण हम देखते हैं कि भारत के आम लोग साइबर ठगी का शिकार बन रहे हैं। भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 14 से 15 प्रतिशत डिजिटल इकॉनमी से संचालित होता है। लोग भी अब लेन-देन के लिए फोन-पे, गूगल-पे आदि का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से भी साइबर सिक्योरिटी अर्थव्यवस्था का एक अहम बिंदु है। पिछले कुछ वर्षों में साइबर ठगी के अलग-अलग प्रकार हमें देखने को मिले हैं। प्रायः हर रोज अखबार पलटते हुए कोई न कोई खबर साइबर ठगी की मिल ही जाती है। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्यों के साथ-साथ 19 मेट्रो शहरों में साइबर अपराध के मामलों में तेज वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट बताती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराधों में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। साइबर अपराध के कारण महिलाओं से संबंधित साइबर अपराध में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पोर्नोग्राफी के वीडियो बनाकर अपलोड करना, अश्लील चैट, अवांछित एसएमएस, सेक्स-टोर्सन इत्यादि मामले शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 35 प्रतिशत महिलाओं ने ही अपने खिलाफ हुए साइबर अपराध की शिकायत की थी।

वहीं साइबर अपराध से पीड़ित 46.7 फीसदी महिलाओं ने किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज न कार्रवाई व 18.3 प्रतिशत महिलाओं को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वे साइबर अपराध का शिकार हो रही हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की साइबर अपराध घटना होती है तो 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने भी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षित भारत पहल जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साइबर सिक्योरिटी के गंभीर खतरों को देखते हुए जरूरत है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाए। बच्चों को भी साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समान रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके जागरूक किया जाए। साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

रमेश धवाला

कोच्ड व्यंग्यकार, संभावनाएं अपार

जबसे उनके इधर उधर फ्री में आठ दस व्यंग्य छपे हैं वे अपने को व्यंग्य का पहरुआ समझने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि वे आला दर्जे के व्यंग्यकार हैं। उन्हें लगने लगा है कि इस धरती पर उनका जन्म व्यंग्य के कल्याण के लिए हुआ है। उन्हें लगने लगा है कि साहित्य का कल्याण आज की डेट में जो कोई कर सकता है तो बस, व्यंग्य ही कर सकता है। कविता, कहानी आज की तारीख में साहित्य का बेड़ा पार नहीं लगा सकते तो साहित्यकार का क्या खाक लगाएंगे। अब समय आ गया है कि उन्हें व्यंग्य का मसीहा हो जाना चाहिए। व्यंग्य का युगपुरुष हो जाना चाहिए। वैसे आदमी को मसीहा बनते देर नहीं लगती। पर आदमी को बनते हुए युगों लग जाते हैं। अतः उन्होंने व्यंग्य में प्राण प्रतिष्ठा करने का इरादा कमर में बांध सबसे कुछ हटकर करने का फितूर दिमाग में बीज कल मुझे फोन लगाया, 'और भाई साहब! क्या कर रहे हो? गैसादि से फ्री हो गए हो क्या?' बहुत गुस्सा आया। मन किया, सारी गैस उनके नाक पर दे मारूं। 'जी हां! फ्री हो गया हूं। फरमाइए! कहिए, कैसे याद किया? कहीं आज फिर फ्री का व्यंग्य छप गया क्या?' 'नहीं भाई साहब! मैं ठहरा घासलेटी व्यंग्यकार। मासलेटी व्यंग्यकारों सी अपनी किस्मत कहां! आप फ्री हों तो आपसे एक मौलिक विमर्श पर विचार विमर्श करना चाहता हूं।' 'करिए बंधु! यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपके मौलिक विमर्श का हिस्सा बनूं।' 'शुक्रिया भाई साहब! मुझे अपना कीमती बेकार का समय देने के लिए। तो भाई साहब! बात ये है कि मैं व्यंग्य का वेलविशर होने के नाते व्यंग्य के कल्याण के लिए जल्द ही व्यंग्य कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की सोच रहा हूं ताकि आने वाली व्यंग्यकारों की नस्लें मुझे व्यंग्य कोचिंगनेमि के नाम से याद करें।' 'माफ करना बंधु! जब व्यंग्य के अनपढ़ों द्वारा भी धड़ल्ले से सफल व्यंग्य लिखा जा रहा है तो ऐसे में व्यंग्य कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों?' 'जी भाई साहब! वह इसलिए कि बिन कोचिंग के आज जीव कुछ नहीं कर सकता सिवा राजनीति के।

आज तो बंदे को जो रोटी कमाने की तो छोड़ो, रोटी खाने की भी कोचिंग न दी जाए तो वह रोटी मुंह के बदले कान से घुसाने लग जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोचिंग का आज हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो अब रही बात केवल व्यंग्य की ही कोचिंग कि क्यों, तो भाई साहब! जिस तरह इंजीनियरिंग में जितनी वैल्यू आज कंप्यूटर साइंस की डिग्री वाले की है उतनी मैकेनिकल डिग्री वाले की नहीं। हालांकि हैं दोनों की चार साल की डिग्रियां ही। इसी तरह साहित्य की फील्ड में जितनी वैल्यू आज व्यंग्य की है उतनी कहानी, कविता की नहीं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि व्यंग्य लिखने वाला भी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर की तरह हाथों हाथ उठे, अच्छे पारिश्रमिक के साथ। खाली शौहरत से पेट नहीं भरा करते भाई साहब! माफ करना! आपके पास व्यंग्य तो है, पर व्यंग्य की बाजारू कोचिंग नहीं। कोचिंग गधे को भी स्मार्ट बनाती है। यह दौर स्मार्टनेस का दौर है, समर्पण का नहीं। अब आपके पास व्यंग्य तो है, पर व्यंग्य लेखन की कोई कोचिंग लोचिंग नहीं जो आपको स्मार्ट बनाए। होती तो स्मार्ट व्यंग्य लिखने से पहले उसे बेच मस्त जीवन जी रहे होते। मेरा मतलब, हिंदी में व्यंग्यकार तो बहुत हैं, पर अनकोच्ड! जिस कारण उस तरह का हाई पेड व्यंग्य लिखा नहीं जा रहा जिस तरह का व्यंग्य असल में लिखा जाना चाहिए। इससे व्यंग्य का अपकर्ष हो रहा है। व्यंग्यकारों की भीड़ के बावजूद अभी भी कोच्ड व्यंग्यकारों की अपने यहां बहुत शॉर्टेज चली है। अगर व्यंग्यकार मेरे इंस्टीट्यूट का कोच्ड होगा तो वह बाजार डिमांड के हिसाब से व्यंग्य प्रोड्यूस करेगा। वह व्यंग्य की बाजारु बारीक से बारीक बारीकियों से लेस होगा। अपने व्यंग्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं छात्रों को विसंगति क्रैक करने के ऐसे ऐसे उंडे बताऊंगा कि उसे विसंगति क्रैक करने में दिनों न लगे। तब वह व्यंग्य लिखते वक्त विसंगति पर माथापच्ची कर समय बेकार न करेगा। विसंगति दिखी, क्रैक की और व्यंग्य तैयार। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यंग्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से व्यंग्य लिखने की कोचिंग लेकर व्यंग्य लिखने वाले का कूड़ा व्यंग्य भी उत्कर्ष नहीं, चर्मोत्कर्ष पर जाए। जब मेरे इंस्टीट्यूट से व्यंग्य की प्रापर कोचिंग ले मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट व्यंग्य के कॉलमों में उतरेगा तो जहां एक ओर व्यंग्य का निश्चित ही कल्याण होगा, वहीं दूसरी ओर मुझ व्यंग्यात्मा को भी यह सोच परमशांति मिलेगी कि इस जन्म में मैंने व्यंग्य के लिए कुछ तो किया', कह उन्होंने लंबी आह भरी और फोन काट दिया।

अशोक गौतम

उचित मूल्य की दुकानों से भी आनलाइन हो सकेगी खरीद

उचित मूल्य की दुकानों को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की देखरेख में चल रहे ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) प्लेटफार्म पर लाने की पहल की गई है। यह पायलट पहल हिमाचल प्रदेश की 11 एफपीएस में शुरू की गई जिनमें ऊना की पांच एफपीएस और हमीरपुर जिले की छह एफपीएस शामिल हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। उचित मूल्य की दुकानों को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की देखरेख में चल रहे ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) प्लेटफार्म पर लाने की पहल की गई है। इस दिशा में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों की उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को ऑन-बोर्ड करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लांच की।

दुकानदारों की आय को बढ़ाने का उद्देश्य

यह पायलट पहल हिमाचल प्रदेश की 11 एफपीएस में शुरू की गई जिनमें ऊना की पांच एफपीएस और हमीरपुर जिले की छह एफपीएस शामिल हैं। पहली बार उचित मूल्य की दुकानें ओएनडीसी प्लेटफार्म से जुड़ी हैं। इस पहल का उद्देश्य उचित मूल्य के दुकानदारों की आय को बढ़ाना है।

सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त अनाज के अलावा भी इन दुकानों में कई वस्तुएं बिकती है या वे दुकानदार बेच सकते हैं। ओएनडीसी से जुड़ने पर लोग इन दुकानों से सरकारी सब्सिडी के अतिरिक्त बेचे गए सामान को आनलाइन मंगा सकेंगे।

चोपड़ा ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य लाभार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ-साथ एफपीएस डीलरों के लिए आय सृजन के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना भी है। जिन लाभार्थियों को ऑनलाइन खरीदारी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे भी अपनी ओर से ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ऐसे एफपीएस डीलर के साथ संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही इस पायलट पहल की सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी इस माडल को लागू किया जा सकता है।

तेल कंपनियों ने छह महीने कमाया बंफर मुनाफा

कीमतों में कटौती के सिवाय इनर्जी वीक में हो रही हर चीज पर बात

इंडिया इनर्जी वीक (आइईडब्लू) में दुनिया के 120 देशों के प्रतिनिधि व ऊर्जा सेक्टर के विशेषज्ञ आये हुए हैं। यहां पर ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हर विषय जैसे ऊर्जा सुरक्षा ग्रीन हाइड्रोजन के भविष्य विदेशों में हाइड्रोकार्बन संपत्ति अधिग्रहित करने की रणनीति बड़ी तेल कंपनियों की तरफ से ग्रीन ऊर्जा को अपनाने की रणनीति आदि पर पर चर्चा हो रही है।

> सरकारी तेल कंपनियां किस कीमत पर तेल खरीद रही हैं और खुदरा कीमत तय करने में किस कीमत को आधार बनाया जा रहा है, यह पूरा फार्मूला ही बहुत ही उलझा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के डाटा के हिसाब से जाएं तो चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत ने जून, 2023 में सबसे सस्ती कीमत (औसत मासिक कीमत) पर 74.93 डॉलर प्रति बैरल की दर से क्रूड खरीद की जबकि सबसे महंगी कीमत सितंबर, 2023 में 93.54 डॉलर प्रति बैरल की दी है।

बेतुल (गोवा)। गोवा के बेतुल में स्थित ओएनजीसी के कैंपस में चल रहे इंडिया इनर्जी वीक (आइईडब्लू) में दुनिया के 120 देशों के प्रतिनिधि व ऊर्जा सेक्टर के विशेषज्ञ आये हुए हैं। यहां पर ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हर विषय जैसे ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन के भविष्य, विदेशों में हाइड्रोकार्बन संपत्ति अधिग्रहित करने की रणनीति, बड़ी तेल कंपनियों की तरफ से ग्रीन ऊर्जा को अपनाने की रणनीति आदि पर पर चर्चा हो रही है लेकिन उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है।

यह विषय है देश में पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती का मामला। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले छह महीनों में सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों को हुए भारी मुनाफे (संयुक्त शुद्ध लाभ-तकरीबन 68,000 करोड़ रुपये) के बावजूद उनकी तरफ से आम जनता को राहत देने की कोई बात नहीं की जा रही।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुनाफा

कुछ हफ्ते पहले तक पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा कमाने वाली इन तीनों कंपनियों (आइओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल) का कहना है कि उन्हें अब डीजल बिक्री में घाटा हो रहा है। देश में पेट्रो उत्पादों के सस्ता होने की संभावना से जुड़े सवाल पर सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी खुल कर कुछ नहीं बोल रहे।

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि यह एक तार्किक सवाल है लेकिन इसका जबाव तेल कंपनियां उचित समय पर देंगी। सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं करती। उनका यह कहना है कि हाल में तेल कंपनियों को जो मुनाफा हुआ है वह कोई बहुत ज्यादा नहीं है।

वैसे भी वैश्विक हालात बहुत ज्यादा अस्थिर हैं जिसकी वजह से कोई भी फैसला करना आसान नहीं है। जहां तक बंपर मुनाफे का सवाल है तो अगर ऐसी ही स्थिति चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2024) में भी रहती है तो कंपनियां कीमतों में संशोधन कर सकती हैं।

सरकारी तेल कंपनियां किस कीमत पर तेल खरीद रही हैं और खुदरा कीमत तय करने में किस कीमत को आधार बनाया जा रहा है, यह पूरा फार्मूला ही बहुत ही उलझा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के डाटा के हिसाब से जाएं तो चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत ने जून, 2023 में सबसे सस्ती कीमत (औसत मासिक कीमत) पर 74.93 डॉलर प्रति बैरल की दर से क्रूड खरीद की जबकि सबसे महंगी कीमत सितंबर, 2023 में 93.54 डॉलर प्रति बैरल की दी है।

सरकारी तेल कंपनियों खूब मुनाफा

पहले के दस महीनों में सिर्फ दो महीने ही 90 डॉलर से ज्यादा कीमत दी गई है। जनवरी में यह कीमत 79.22 डॉलर प्रति बैरल की रही है। कहने की जरूरत नहीं कि जब अप्रैल से सितंबर, 2023 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड 75 डॉलर के करीब थी तब सरकारी तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया है। यहीं वजह है कि पहले नौ महीनों में तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों का शुद्ध मुनाफा इसके पिछले वर्ष के दौरान इनकी समूचे राजस्व (39,356 करोड़ रुपये) से ज्यादा रही है।

वर्ष 2022-23 में इन्हें कुल 21,201 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कंपनियों ने अप्रैल, 2022 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बदलाव 06 अप्रैल, 2022 को किया गया था और तब बताया गया था कि घरेलू बाजार में पेट्रोल की बिक्री में 17 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 26-27 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था।

मई, 2022 में केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके तेल कंपनियों को 10 रुपये प्रति लीटर की राहत दी थी। उसके बाद से घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि दो वर्षों में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में कमी हुई है। जबकि इस दौरान दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों मे भारी अस्थिरता रही है और वहां इनकी किल्लत भी हुई है। भारत में कहीं भी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है।

इनसाइड

NSE की कंपनियों में नए स्तर पर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी, यहां जानें डिटेल

प्राइम इन्फोबेस के डाटा के अनुसार एनएसई में लिस्टेड कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 8.81 प्रतिशत के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 30 सितंबर 2023 में इन कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.73 प्रतिशत थी। बीमा कंपनियों ने 5622 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। इसमें एलआइसी का बड़ा हिस्सा रहा है।

नई दिल्ली। एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 8.81 प्रतिशत के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। प्राइम इन्फोबेस के डाटा के अनुसार, 30 सितंबर 2023 में इन कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.73 प्रतिशत थी। बीती तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने एनएसई की कंपनियों मे 58,198 करोड़ रुपये का मजबूत निवेश किया है।

एलआईसी की घटी निवेश हिस्सेदारी

डाटा के अनुसार, 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में एलआईसी की निवेश हिस्सेदारी घटकर 3.64 प्रतिशत रही है। यह इसका सर्वकालिक निचला स्तर है। 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में एलआइसी की निवेश हिस्सेदारी 3.73 प्रतिशत थी।

फोन में नहीं चल रहा है इंटरनेट, घबराएं नहीं अब आसानी से ऑफलाइन हो जाएगी यूपीआई पेमेंट

UPI Payment बीते दिन कई लोगों को यूपीआई पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। NPCI ने ग्राहकों को ऑफलाइन यूपीआई भुगतान करने की अनुमति दी है। आइए जानते हैं कि आप ऑफलाइन तरीके यानी कि बिना इंटरनेट के कैसे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आप बटन वाले फोन से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं।

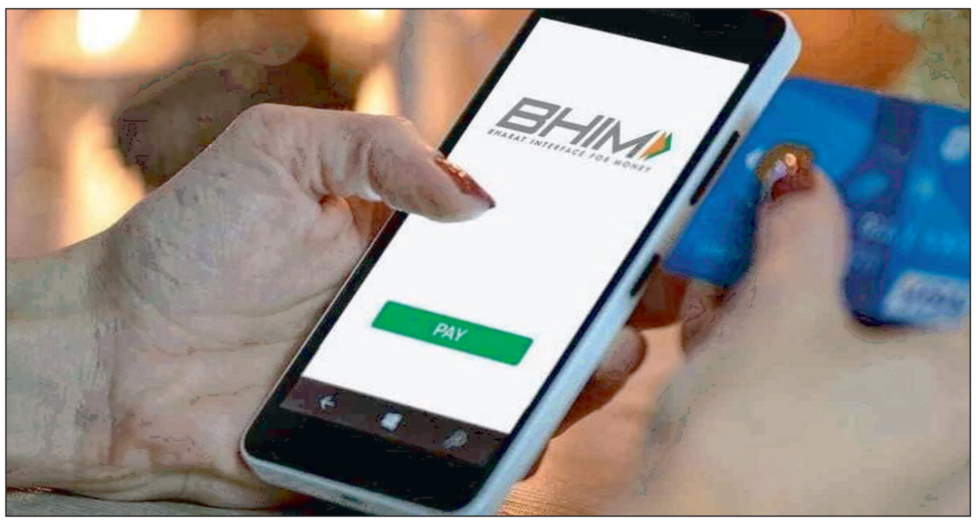

नई दिल्ली। बीते दिन कई यूपीआई ऐप्स (UPI Apps) पर पेमेंट होने में परेशानी आ रही थी। कई बार यह समस्या नेटवर्क प्रोब्लम या फिर हाई-स्पीड में इंटरनेट ना चलने की वजह से होती है।

ऐसे में अगर कभी इंटरनेट ना चले तो क्या यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) नहीं किया जा सकता है? जी नहीं, आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ग्राहकों को ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा दी है।

आप बटन वाले फोन से भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब यूपीआई पेमेंट के लिए आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। हालांकि, ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट (Offline UPI Payment) आप केवल उस मोबाइल नंबर से कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो।

ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट कैसे करें

आपको अपने फोन में *99# डायल करके कॉल करना है।

इसके बाद आपको₹1₹ ऑप्शन ₹Send Money₹ को सेलेक्ट करना है।

अब आप यूपीआई आईडी (UPI ID) दर्ज करें। आप बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर या फिर बैक अकाउंट नंबर भी दर्ज कर सकते हैं।

इसके बाद आपको उतना अमाउंट डालना है जितना आप भेजना चाहते हैं। बता दें कि आप ऑफलाइन पेमेंट में केवल 5,000 रुपये तक ही भेज सकते हैं।

इसके बाद यूपीआई पिन दर्ज करें।

यूपीआई पिन (UPI Pin) दर्ज करने के बाद पेमेंट पूरा हो जाएगा।

ऑफलाइन पेमेंट से पहले फोन को करें सेटअप

अगर आप भी ऑफलाइन पेमेंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने फोन को सेटअप करना होगा। चलिए, जानते हैं कि सेटअप का प्रोसेस क्या है।

आपको अपने फोन से *99# डायल करना है।

इसके बाद आप अपनी भाषा चुनें।

अब आप टेक्स्ट फील्ड में अपने बैंक का IFSC कोड दर्ज करें।

इसके बाद आपको ₹1₹ या ₹2₹ या अन्य विकल्प में से कोई सेलेक्ट करना है। इसमें बैंक अकाउंट नंबर को पेमेंट के लिए सेटअप किया जा सकता है।

अब आप अपने डेबिट कार्ड (Debit Card) के आखिरी 6 अंक भरें और कार्ड की एक्सपायरी डेट दर्ज करें।

इसके बाद यह सेटअप प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

चावल 29 रुपये और दाल 60 रुपये प्रति किलो बेच रही सरकार, जानें कहां से करें खरीदारी

सरकार Bharat ब्रांड के तहत रियायती दर पर अनाज बेच रही है। दरअसल पिछले साल खुदरा आनाज की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाया है। अब Bharat ब्रांड के जरिये आटा दाल चावल बेचा जा रहा है। हाल में आए रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा पसंद Bharat Dal को किया जा रहा है।

नई दिल्ली। खुदरा आनाज की कीमतों में तेजी देखने के बाद सरकार 'Bharat' ब्रांड के तहत रियायती दर पर अनाज बेच रही है। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 'Bharat Dal' देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला दाल है।

भारत दाल

Bharat Dal में चना दाल बेचा जाता है। इसमें 1 किलो पैक का दाल केवल 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। वर्तमान में यह NAFED, NCCF, केन्द्रीय भंडार और सफल द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं।

राज्य सरकारें राज्य-नियंत्रित सहकारी समितियों और निगमों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं भी वितरण के लिए इस दाल का इस्तेमाल किया जाता है। आप 'Bharat' ब्रांड का आटा और चावल भी खरीद सकते हैं।

'भारत चावल'

मंगलवार को मोदी सरकार ने 'भारत चावल' को लॉन्च किया था। सरकार ने शुरुआत के लिए इस ब्रांड के तहत 5 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) चावल निर्धारित किया है। इसका मूल्य 29 प्रति किलो है। इसमें 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग उपलब्ध है।

इसे मोबाइल वैन और भौतिक दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इसके अलावा इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि भारत दाल और भारत आटा की तरह भारत चावल भी सफल हो।

'भारत आटा'

सरकार 'Bharat' ब्रांड के तहत रियाती दर पर आटा भी बेच रही है। यह 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। सरकार ने सबसे पहले 'Bharat' ब्रांड के तहत आटा बेचना शुरू किया था।

'भारत आटा' सबसे पहले खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक खरीदारों को बेचा जाता था। इसकी सफलता के बाद अब दाल और चावल भी इसके जरिये बेचा जा रहा है।

चढ़ गया सोना और लुढ़क गई चांदी, जानें क्या है आज आपके शहर में सोना-चांदी के दाम

परिवहन विशेष न्यूज

देश में सोना-चांजी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह निवेश के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में गोल्ड या सिल्वर खरीदने से पहले आपको उसके लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना-चांदी कितने रुपये में मिल रहा है।

नई दिल्ली। बुधवार के कारोबारी सत्र में सोने-चांदी के नए दाम जारी हो गए हैं। गोल्ड-सिल्वर को काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह निवेश का भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आज सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के दाम में नरमी देखने को मिली है। अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने वाले हैं तो आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। चलिए, जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना-चांदी कितने रुपये में मिल रही है।

चढ़ गए सोने के दाम

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में बढ़त के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमतें 170 रुपये उछलकर 63,370 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। पिछले कारोबार में गोल्ड 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,033 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा

विदेशी बाजारों से तेजी का संकेत लेते हुए दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें (24 कैरेट) 170 रुपये बढ़कर 63,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में गिरावट के बीच बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी आई।

कम हो गए चांदी के दाम

आज चांदी 300 रुपये गिरकर 74,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि पिछले बंद में यह 74,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर चांदी मामूली गिरावट के साथ 22.24 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

क्या है आपके शहर में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,330 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,230 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,230 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,820 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,230 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,230 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,330 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,330 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 63,280 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 63,330 रुपये है।

'Paytm मुद्दे से निपटना RBI का काम', वित्तीय सेवाओं के सचिव जोशी बोले- मेरी समक्ष से PPBL बैंक नहीं...

वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को कहा कि पेटीएम मुद्दे से निपटना आरबीआई का काम है। सरकार का फिलहाल इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। विवेक जोशी ने कहा कि यह बैंकों को विनियमित करने वाले नियामक की ओर से की गई कार्रवाई है। हमारा मानना है कि आरबीआई ने उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के हित में कार्रवाई की होगी।

नई दिल्ली। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को कहा कि पेटीएम मुद्दे से निपटना आरबीआई का काम है। सरकार का फिलहाल इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जोशी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) एक छोटी वित्तीय इकाई है और इसमें कोई प्रणालीगत स्थिरता संबंधी चिंता नहीं है। नियमों का पालन न करने समेत विभिन्न चिंताओं के चलते आरबीआई ने पीपीबीएल को 29 फरवरी के किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने पर रोक लगाई है। साथ ही बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।

विवेक जोशी ने कहा कि यह बैंकों को विनियमित करने वाले नियामक की ओर से की गई कार्रवाई है। हमारा मानना है कि आरबीआई ने उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के हित में कार्रवाई की होगी। पेटीएम की पेमेंट एग्रीगेटर सब्सिडियरी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संबंध में जोशी ने कहा कि चीन से निवेश के लिए अनुमति मांगी गई है। आवेदन की समीक्षा चल रही है। जोशी ने कहा, जहां तक मेरी समक्ष है, पीपीबीएल बैंक नहीं है, जो खातों को स्थानांतरित करेगा। यह कार्य ग्राहकों को करना होगा।

पेटीएम नाम से डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और बीएसई में यह 496.75 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इसी तरह एनएसई में कंपनी के शेयर 9.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 496.25 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। 31 जनवरी को आरबीआई की सख्ती के बाद एक से पांच फरवरी के दौरान तीन कारोबारी सत्रों में पेटीएम के शेयरों में 42 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 20,471.25 करोड़ रुपये की कमी आई थी। लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर तीन प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए थे। बीते दो दिनों की तेजी से कंपनी के पूंजीकरण में 3,720.17 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 9 को बैठक, परखेंगे तैयारियां

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर शुक्रवार को नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांजिट सिस्टम (एनसीआरटीसी), रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की निर्माणाधीन साइट पर बैठक होगी। नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और सितंबर में प्रस्तावित उड़ान को देखते हुए कनेक्टिविटी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर के शहरों से नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचना सुगम और सुरक्षित हो इसके लिए रैपिड रेल, मेट्रो, रेलवे, बस व सड़क मार्ग आदि विकल्पों पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं की प्रगति जानने के लिए ही बैठक होगी। एयरपोर्ट साइट पर होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी बहाने स्थलीय निरीक्षण भी हो जाएगा। उड़ान के लिए ट्रायल शुरू करने पर भी बात हो सकती है। रैपिड रेल/मेट्रो से जोड़ने के लिए गाजियाबाद वाया ग्रेनो वेस्ट, परी चौक व यीडा सिटी से होते हुए एयरपोर्ट तक का रूट फाइनल हो गया है। एनसीआरटीसी को पांच माह में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। रूट का सर्वे करते हुए मिट्टी की जांच भी शुरू कर दी है। चोला स्टेशन से एयरपोर्ट तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बसों का भी संचालन होगा। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक नया हाईवे बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में इन्हीं सब परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 9 फरवरी को समीक्षा बैठक होगी। इसमें प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर सरकार गंभीर है। इसके रैपिड रेल, मेट्रो, रेल व सड़क मार्ग से जोड़ने पर काम चल रहा है।

-डॉ.अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

क्या चुनाव से पहले बीजेपी बिजेड़ी गठबंधन हो गया क्या ?

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य में सत्तासीन बिजेड़ी सरकार की आलोचना करने के बजाय वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मित्र कहकर संबोधित किया । ओडिशा में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो गया है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले शनिवार को आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए ओडिशा आए थे। मोदी के दौरे के दौरान यह उम्मीद की जा रही थी कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बिजेड़ी सरकार और उसके नेताओं की कड़ी आलोचना करेंगे । लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की आलोचना करने के बजाय उन्हें मित्र कहकर संबोधित किया । यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सार्वजनिक भाषणों में बिजेड़ी पर निशाना साधने से बचते रहे । इस अखबार की मुख्य खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे रुख पर चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव से पहले बीजेडी-बीजेपी के बीच चुनावी गठबंधन हो गया है ।

इतना ही नहीं, बिजेड़ी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी यह मौका नहीं छोड़ा । नवीन पटनायक ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की । नवीन पटनायक ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री ने भारत के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है और हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर हैं।मोदी की यात्रा से पहले, सभी की निगाहें उनके सार्वजनिक भाषणों पर थीं, क्योंकि पार्टी के राज्य नेताओं को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री का यह कदम चुनाव से पहले बिज्जद के खिलाफ पार्टी के रुख के लिए माहौल तैयार करेगा। हालांकि राज्य के भाजपा नेता बार-बार मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेता उनके प्रति नरम रहे हैं।

हाल के दिनों में नवीन पटनायक का राजनीतिक आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कई विवादास्पद कानूनों, राष्ट्रपति चुनावों, नीतियों को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार को 10 में से 8 रेटिंग भी दी । नवीन पटनायक के इस रुख से ओडिशा में बिजेड़ी-बिजेपि की नजदीकियों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं ।

अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर ने किया ज़िले के राजकीय चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। जिलेवासियो को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा मरिजो के रोग की जाँच व उपचार में किसी भी प्रकार की देरी ना होने देने के उद्देश्य से ज़िला कलेक्टर श्री टीकम चन्द बोहरा को आज प्राप्त शिकायत के निस्तारण के क्रम में ज़िला कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर श्री मुकेश कुमार मीणा तुरंत मौक़े पर पहुँचे तथा उन्होंने ज़िले के राजकीय चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ अभय धाकड़ व डॉ सौरभ चिकित्सालय में अनुपस्थित पाए गए। अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर श्री मुकेश कुमार मीणा ने बताया की निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित दोनों चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है एवं मरीजो की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के औचक निरीक्षण प्रशासन द्वारा निरंतर होते रहेंगे । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार ज़िले में सरकारी कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण का दौर जारी है तथा किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के अनुपस्थित रहने अथवा राजकार्यों में लापरवाही बरतने पर प्रशासन द्वारा सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

पार्षद प्रतिनिधि ने कक्ष के बाहर लिखा "भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति लापता"

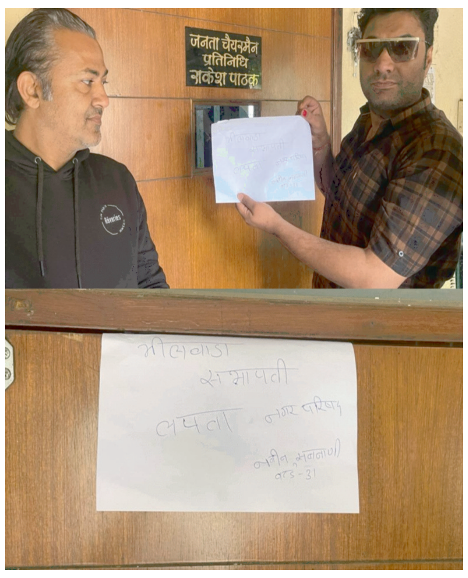

भीलवाड़ा। नगर परिषद वार्ड 31 पार्षद प्रतिनिधि नवीन समनानी ने आज सभापति कक्ष के बाहर लिख दिया ₹भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति लापता₹ नवीन समनानी ने बताया कि पिछले 3 साल से वार्ड में कोई टेंडर नहीं लगा है जो दो टेंडर लगे वह भी अधूरे काम हुए वार्ड में 18 कर्मचारियों में से 6 से 7 कर्मचारी नहीं आ रहे हैं वह मिलीभगत से उनकी तनख्वाह उठ रही है ।वार्ड में सफाई की व्यवस्था सही नहीं है 13सेनेटरी गलियां है उनमें सीसी का टेंडर छोड़ो सफाई नहीं हो पा रही है ।इन मुद्दों को लेकर कई बार लिखित में सभापति राकेश पाठक को दिया गया पर कोई काम नहीं हुआ काम छोड़ो सभापति फोन तक नहीं उठाते हैं जब सभापति पार्षद का फोन नहीं उठाते तो जनता का क्या काम करेंगे जनता ने हमें काम के लिए चुना है जनता का काम तो करना होगा सीवरेज के काम अधूरे पड़े हैं नगर परिषद के पास रोड लाइट तक नहीं है ठेकेदारों को कहना है कि टेंडर नहीं हुआ तो लाइट नहीं है छोटी समस्याओं का समाधान भी सभापति नहीं कर पा रहे हैं। नवीन ने कहा कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कचरा ले नगर परिषद डालेंगे।

भीलवाड़ा आगमन पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का भाजपा ने किया भव्य स्वागत

पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा की स्थिर सरकार जरूरी - कुमावत

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। राजस्थान सरकार में पशुपालन, गोपालन, देवस्थान एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत का आज भीलवाड़ा आगमन पर स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं विधायक उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पीतलिया, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक की विशिष्ट उपस्थिति में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि कैबिनेट मंत्री कुमावत ने इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश में भाजपा की स्थिर सरकार जरूरी है । इसके लिए सभी को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा । उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है और सरकार ने आते ही कई बड़े निर्णय लिए है । कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस की नीति एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है और अभी तक दस हजार से ज्यादा अपराधियों को जेल में डालने का काम सरकार ने किया है । जबकि कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी, महिला एवं दलित अत्याचार चरम पर थे पर उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया । भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे उन पर सरकार बनने के तुरंत बाद अमल शुरू कर दिया चाहे वह गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात हो या 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने के साथ ही हर घर में नल और जल पहुंचाने की योजना पर भी त्वरित गति से कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री राजस्थान में जरूरतमंदों तक पानी, बिजली, चिकत्सा, शिक्षा, सड़कें जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है । भारत सरकार की जिन योजनाओं को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रोक रखा था उन्हें भी शुरू करने का काम राज्य की भाजपा सरकार कर रही है।

स्वागत एवं अभिनंदन के अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री भगवती प्रसाद जोशी राजकुमार आंचलिया, वेदप्रकाश खटीक, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी, बाबूलाल आचार्य, शंकरलाल जाट, मंजू चेचाणी, अविनाश जीनगर, जिला मंत्री गोपाल तेली, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, महावीर समदानी, मनोज बुलानी, आकाश मालावत, मंडल अध्यक्ष मनीष पालीवाल, घनश्याम सिंगीवाल, अनिलसिंह जादौन, मोर्चा अध्यक्ष पूरण डीडवानिया, राजेश सेन, मुकेश चेचाणी, मुकेश शर्मा, उदय कुमावत, आरती कोगटा, मधु शर्मा, मनीष पारीक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

गौरव पुरस्कार अवार्ड तारीख 4 फरवरी 2024 मुंबई सीएसटी सम्मानपत्र अवार्ड गुलाब सलाट एक्शन एक्टर को मिला

लोक गौरव राष्ट्रीय एकात्मता परिषद टीएमजी अनमोल कार्य गौरव पुरस्कार दिनांक 4 फरवरी 2024 मुंबई सीएसटी सम्मानपत्र पुरस्कार हुआ

परिवहन विशेष न्यूज

गरीबी का कहर टूटने के बाद और सालों की मेहनत के बाद गुलाब सलाट एक्शन एक्टर को ऐसे अनेक मिले है फिल्मी अवार्ड लोकगौरव राष्ट्रीय एकात्मता परिषद टी.एम.जी.अनमोल कार्य गौरव पुरस्कार अवार्ड तारीख 4 फरवरी 2024 मुंबई सीएसटी सम्मानपत्र अवार्ड गुलाब सलाट एक्शन एक्टर को मिला है डॉक्टर शैलेंद्र पवार सलमा खान नासिर खान जाकिर खान स्पेशल थैंक यू भारत का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ नई दिल्ली 4 जुलाई 2023 एमपी जबलपुर मैं सम्मानपत्र दिया गया अवार्ड नेशनल एचिवमेट तारीख 4 जून 2023 को मुंबई से मिला पुरस्कार दिल्ली बॉलीवुड सीने रिपोर्टर अवार्ड नागपुर गौरव महाराष्ट्र पुरस्कार मुंबई जनगौरव कार्य दर्पण पुरस्कार वडोदरा सीने मीडिया अवार्ड वाइब्रेट गुजराती फिल्म अवार्ड से नवाजा है गुलाब का जीवन परिचय गुलाब एक्शन एक्टर आनंद गुजरात की पैदाइश है गुलाब के माता पिता बहुत ही गरीब थे और उनका पूरा जीवन चारपाई के तंबू में गुजार दिया था लेकिन गुलाब के पिता तम्मा भाई सलाट एक हाथ मजदूरी कर कर अपने बेटे को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में थे और उसमें एक नाम था गुलाब सलाट का जो 8 वर्ष की उम्र से ही फिल्म बॉलीवुड का लगाव था कि मैं एक बार फिल्मों में काम करूंगा पापा को यह बोला था पापा ने वही बात को लेकर मेहनत करना चालू कर दिया रात दिन मजदूरी कर कर अपने बेटे को एक अकैडमी में जॉइनिंग करवा दिया मार्शल आर्ट कराटे ऑल इंडिया वाडो काई कराटे डो एकेडमी इंडिया इंटरनेशनल मै करीबन 5 साल लगातार मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कराटे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट की डिग्री हासिल की और गुलाब अपने डांस की कड़ी मेहनत कर कर बाग बगीचों में प्रैक्टिस करते थे बिना मास्टर के जिमनास्टिक और डांस की ट्रेनिंग लेने गए हैदराबाद वहां से कड़ी मेहनत कर कर 1 साल के बाद डिग्री मिली पिता तम्मा भाई का देहांत हो गया पिता के जाने के बाद हालात ऐसे थे आनंद रामनगर की स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे मैत्री विद्यालय रामनगर हालात ऐसे थे आठवीं कक्षा तक पढ़ाई छोड़ना पड़ा घर में काफी परेशानियां बढ़ने लगी हर जगह जगह हर स्टेट में गए गुलाब और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपने काम के लिए गुजारिश की लेकिन नाकाम रहा अपने शहर वापस आए और फिर अपनी ट्रेनिंग करना चालू कर दिया अपने पापा का शहर का नाम रोशन करुंगा हिम्मत नहीं हारे किस्मत ऐसी जगी किस्मत सीरियल जय जय जग जननी दुर्गा मां जय बजरंगबली फिल्म में काम करने की शुरुआत सीरियल से हुई छोटी बड़ी 17 फिल्मों में काम मिला हिंदी गुजराती भोजपुरी अप कमिंग फिल्म भविष्य का सुपरस्टार जिसमें लीड हीरो का रोल करेंगे जिसकी शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली बैंगलोर एंड कोलकाता मै होगी गुलाब रात दिन कम से कम 8 घंटा मेहनत और प्रैक्टिस लगातार कराटे मार्शल आर्ट जिमनास्टिक योगा बॉडी स्टंट ब्रेक डांस लाठी नानचाकू तलवार राइफल शूटिंग एवं फिल्मी एक्टिंग करते थे अपने फिल्म के गुलाब एक्शन एक्टर अपने पिता का नाम रोशन करने का सपना बहुत जल्द पूरा करूंगा आज गुलाब सलाट ऐक्शन ऐक्टर नाम मीडिया के वजह से पूरे भारत में अपनी एक अच्छी पहचान बनाया।

मातंग ऋषि की पुत्री श्रृंगार लहरी की प्रस्तुती में श्रृंगार रस को किया जीवन्त

वर्कशॉप ड्रमोस्ट्रेशन कार्यक्रम का तीसरा दिन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। स्पिक मैके (सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्युजिक एण्ड कल्चरल अमंग्स्ट यूथ) द्वारा चल रहे जिले के सरकारी विद्यालयो मेंवर्कशॉप ड्रेमोस्टेशन कार्यक्रम के तीसरे दिन भरतनाट्यम नृत्यांगना तान्या सक्सेना की प्रथम प्रस्तुती प्रातः 10 बजे रा.उ.मा.वि. संतोकपुरा द्वितीय प्रस्तुती रा.उ.प्रा.वि. कीरखेड़ा में हुई ।जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश पालिया ने बताया कि तान्या ने अपने कार्यक्रम की शुरूआत हस्त मुद्राओ से करते हुये विभिन्न मुद्राओं से सरस्वती, गजानन, शिव, पार्वती आदि स्वरूपों को बनाते हुये, श्रृंगार रस की प्रस्तुति में ऋषि मातंग की पुत्री श्रृंगार लहरी के सौंदर्य को जीवन्त करते हुये श्रृंगार, वाद्ययंत्र, रूप सौन्दर्य आदि को दिखाया। साथ ही भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वर्णित नायक एवं नायिका भेद से भेंद बताते हुये देवी एवं देवाओं में भिन्नता दिखाई। साथ ही छात्र-छात्राओं को मंच पर बुलाकर भरतनाट्यम में भूमि प्रणाम सिखाया, अंत में दोनों विद्यालयों के संस्था प्रधान भगवान सिंह एवं शशि शर्मा ने कलाकार को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया।

मस्जिद गिरा कर गुरुद्वारा रकाबगंज का हुआ था निर्माण: मनजिंदर सिंह सिरसा

गुरुद्वारा रकाबगंज के निर्माण को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा प्रकाशित पुस्तक का हवाला देते हुए कहा था कि सिख योद्धा बाबा बघेल सिंह ने 1783 में मस्जिद ध्वस्त कर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का निर्माण किया था।

नई दिल्ली। गुरुद्वारा रकाबगंज के निर्माण को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा प्रकाशित पुस्तक का हवाला देते हुए कहा था कि सिख योद्धा बाबा बघेल सिंह ने 1783 में मस्जिद ध्वस्त कर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का निर्माण किया था।

उनके इस बयान का शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना व अन्य सिख नेताओं ने विरोध किया है। उन्होंने सिरसा पर सिख इतिहास को गलत तरह से प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए श्री अकाल तख्त के जत्थेदार कार्रवाई करने की मांग की है।

सिरसा का किया समर्थन

डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने सिरसा के बयान का समर्थन करते हुए श्री अकाल तख्त से सरना के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सिरसा ने कार्यक्रम में कहा था कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वही स्थान है, जहां गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का अंतिम संस्कार हुआ था।

मुगलों ने गुरघर को हटाकर बनाई मस्जिद

गुरु गोविंद सिंह वर्ष 1707 में दिल्ली आकर इस स्थान पर गुरुघर बनवाया था। मुगल शासक द्वारा उस गुरुद्वारा को हटाकर मस्जिद बना दी गई थी। वर्ष 1783 में दिल्ली फतेह के बाद बाबा बघेल सिंह ने मुगल शासक सुल्तान शाह आलम को कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पर गुरुद्वारा बनेगा। उन्होंने मस्जिद ध्वस्त कर गुरुद्वारा का निर्माण किया था।

सरना का कहना है कि सिरसा सिख इतिहास की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इससे सिख संगत में रोष है। शिअद बादल के नेता जीके ने कहा कि सिरसा को कुछ बोलने से पहले तथ्य की पड़ताल करनी चाहिए। पहले भी श्री अकाल तख्त से फटकार लग चुकी है।

क्या है रकाबगंज गुरुद्वारा की कहानी

उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का जहां बलिदान हुआ था, वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। जहां धड़ का संस्कार हुआ था वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। गुरु गोविंद सिंह 1707 में यहां आकर इन दोनों स्थानों की निशानदेही की थी। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वाले स्थान को लेकर 1783 में विवाद हुआ था और उस समय खोदाई की गई तो वहां अस्थियां निकली थी उसके बाद वहां गुरुद्वारा बनाने का निर्णय हुआ।

बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आहलुवालिया और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने वहां गुरुद्वारा बनवाया, लेकिन कोई मस्जिद नहीं गिराई गई गई थी। गुरुद्वारा के पास एनडीएमसी कार्यालय को आज भी रकाबगंज मस्जिद कहा जाता है। वहीं, कालका का कहना है कि सिखों की सर्वोच्च संस्था एसजीपीसी द्वारा 2018 में प्रकाशित पुस्तक शहीदी जीवन (गुरबख्श सिंह लिखित) के पेज नंबर 32 पर स्पष्ट लिखा है कि बाबा बघेल सिंह ने मस्जिद ध्वस्त कर गुरुद्वारा साहिब स्थापित किया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023